

10

राज्यों का शासन

राज्यपाल

- किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह वर्णन है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा?
- अनुच्छेद 153 में
- यद्यपि राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, परंतु राज्यपाल पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? - राष्ट्रपति को
- किस संविधानिक संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? - सातवें संविधानिक संशोधन 1956 द्वारा
- राज्यपाल के बेतन का निर्धारण कौन करता है? - संसद
- राज्यपाल को पद से हटाने के लिए संविधान में कितने कारण बताये गये हैं? - कोई नहीं
- किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन नहीं है, बल्कि यह एक संविधानिक पद है? - हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक अनुच्छेद 166(1) के तहत राज्य के समस्त कार्यकारी कार्य किसके नाम से सम्पन्न होते हैं?
- राज्यपाल के नाम से क्या संविधान में राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान है? - नहीं
- संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? - अनुच्छेद 154(1)
- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? - अनुच्छेद 155
- किस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध दिये गये हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करेगा, वह राष्ट्रपति को सम्बोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकेगा, दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए पांच वर्ष तक अपने पद पर रहेगा? - अनुच्छेद 156
- अनुच्छेद 157 के मुताबिक कोई व्यक्ति राज्यपाल होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और कम से कम उसकी आयु कितनी हो? - 35 वर्ष
- किसी राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? - आयु सीमा नहीं है
- किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तब उस राज्यपाल को संदेश उपलब्धियां एवं भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवर्तित किये जायेंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें? - अनुच्छेद 158(3क)
- अनुच्छेद 158(3क) को किस संविधान संशोधन की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित किया गया? - सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956
- अनुच्छेद 159 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? - उच्च न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश
- संविधान में कुछ रिस्तियों में राज्यपाल को स्वविवेक से कार्य करने की बात वर्णित है। क्या राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार के किसी अधिकार का उल्लेख है? - नहीं
- जब कभी किसी राज्य विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब राज्यपाल किस आधार पर निर्णय करता है कि किस व्यक्ति या दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाये? - अपने विवेक के अनुसार
- राज्यपाल को कुछ दंडों तथा दंडादेशों को क्षमा, निलम्बित या परिवर्तित करने की शक्ति दी गयी है। यह शक्ति राष्ट्रपति के समान है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? - अनुच्छेद 161

भाग-6

राज्य (अनुच्छेद 152-237)

अध्याय-1/साधारण

- अनुच्छेद 152: परिभाषा

अध्याय-2

कार्यपालिका (*The Executive*)

(अनुच्छेद 153-167)

राज्यपाल (*The Governor*)

(अनुच्छेद 153-162)

- अनुच्छेद 153: राज्यों के राज्यपाल

● अनुच्छेद 154: राज्य की कार्यपालिका शक्ति

● अनुच्छेद 155: राज्यपाल की नियुक्ति

● अनुच्छेद 156: राज्यपाल की पदावधि

● अनुच्छेद 157: राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं

● अनुच्छेद 158: राज्यपाल के पद के लिए शर्तें

● अनुच्छेद 159: राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

● अनुच्छेद 160: कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन

● अनुच्छेद 161: क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति

● अनुच्छेद 162: राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

(अनुच्छेद 163-164)

● अनुच्छेद 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

● अनुच्छेद 164: मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

राज्य का महाधिवक्ता

(Advocate General for the State)

● अनुच्छेद 165: राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन

(अनुच्छेद 166-167)

● अनुच्छेद 166: राज्य की सरकार के कार्य का संचालन

किंतु NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- मृत्यु दंड को माफ करने का राष्ट्रपति के पास अन्य अधिकार है चाहे वह केन्द्रीय विधि के तहत हो या राज्य विधि के तहत। इस मामले में राज्यपाल का अधिकार कैसा है? - **मोर्मिन**
- राज्यपाल उस अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है, घटा सकता है तथा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, जिसे राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध करने पर दंड मिला हो। राज्यपाल अपने इस अधिकार का प्रयोग किन विषयों में नहीं कर सकता? - **जो संघ सरकार की कार्यपालिका के अधीन हों**
(नोट: राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग मुकदमे की सुनवाई के आरम्भ से पूर्व, उसके बीच अथवा उसके बाद कभी भी कर सकता है।)
- किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय की गयी है, परंतु राज्यपाल के लिए नहीं? - **42वां संविधान संशोधन (1976)**
- किसकी स्वीकृति के बाद ही राज्य विधानमंडल द्वारा पास हुआ विधेयक कानून बन पाता है? - **राज्यपाल की**
- धन विधेयकों को राज्यपाल स्वीकृति देने से इंकार नहीं कर सकता; परंतु साधारण विधेयकों को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। यदि विधानमंडल साधारण विधेयक को दोबारा पास कर दे, तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। राज्यपाल कुछ विधेयकों को किसकी स्वीकृति के लिए भी रख सकता है? - **राष्ट्रपति के लिए**
- किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? - **अनुच्छेद 213 के अनुमार्ग**
- राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के द्वारा जारी किये गये अध्यादेश का अधिकतम मात्र समय होता है? - **7.5 माह**
- अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति के प्रयोग को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह कथन सत्य है या असत्य? - **मन्त्र**
- लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है किंतु इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा तभी करेगा जब? - **सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के जांच के उपरान्त अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रेपित कर दिया हो।**
- राज्य लोक सेवा आयोग और महालेखा निरीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजते हैं। राज्यपाल इन रिपोर्टों को किसके समक्ष रखता है? - **विधानमंडल**
- भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में कौन-से ऐसे दो पद हैं जो अपने पद की शपथ लेते समय संविधान के संरक्षक के रूप में शपथ लेते हैं? - **राष्ट्रपति एवं राज्यपाल**
- राष्ट्रपति को वे कौन-से अधिकार हैं जो राज्यपाल को नहीं प्राप्त हैं? - **कूटनीतिक, सैनिक एवं आपातकालीन शक्तियां**
- राज्यपाल को सैनिक न्यायालय द्वारा दिये गये कौन-से दंड को माफ करने का अधिकार नहीं है? - **मृत्युदंड का अधिकार**
- संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकता है? - **अनुच्छेद 200**
- किस अनुच्छेद के अनुसार, यदि किसी मुद्दे को लेकर यह प्रश्न उठे कि यह कार्य राज्यपाल के विवेकाधीन है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही इस दिशा में अंतिम होगा? - **अनुच्छेद 163(2)**
- राज्य विधानमंडल के वर्ष की प्रथम बैठक एवं चुनावों के बाद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? - **राज्यपाल**
- कौन-सा विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रारम्भ किया जा सकता है? - **धन विधेयक**
- अनुच्छेद 207 के तहत धन एवं वित्त विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किये जाते हैं, जबकि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण दोनों सदनों में रखवाता है? - **अनुच्छेद 202 के तहत**
- राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। यदि संकट के समय आवश्यकता पड़े, तो राज्यपाल इसमें से आवश्यकतानुसार व्यय कर लेता है और बाद में किससे उस व्यय की स्वीकृति ले लेता है? - **राज्य विधानमंडल से**

- **अनुच्छेद 167:** गन्धपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

निखल राज्यपाल क्यों?

राज्यपाल का चुनाव न तो मीधे आम लोगों द्वारा किया जाता है और न ही काउंसिल विग्रह रूप से गठित निर्वाचक मंडल उसका चुनाव करता है। उसके विपरीत गन्धियों के गवर्नर की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से गढ़पति द्वारा की जाती है, जिसके कारण उसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। संविधान निर्माण के समय ममता र्यान्डिन ने यह निर्णय सर्विधान सभा पर छाड़ दिया था कि देश में गन्धपालों के लिए चुनाव किये जाने चाहिए या उसका नामांकन किया जाना चाहिए। इस विषय पर मार्विधान सभा का मानना था कि गन्धपालों के चयन के लिए चुनाव किया जाना चाहिए, परंतु राज्यपाल और मुख्यमंत्री की गाँधियों के बीच टकराव की आशंका ने गन्ध में राज्यपाल के नामांकन की प्रणाली को जन्म दिया। इसके विपरीत यदि गन्धपाल प्रत्यक्ष मत द्वारा निर्वाचित होता तो वह अपने आपको मुख्यमंत्री में बदल समझता, व्यांकि मुख्यमंत्री तो एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। फलत: गन्धपाल और मुख्यमंत्री के बीच वारंवार मंबद्ध दंघने की मिलते। इसके अलावा चुनाव होने पर उसे व्यक्तिगत मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता। साथ ही, सत्तारूप दल स्वभावगत रूप से राज्यपाल के पद के लिए ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेगा जो भावी मुख्यमंत्री की तुलना में श्रेष्ठतर नहीं है। फलस्वरूप गन्ध को दल का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं मिल पायेगा। इसने तरफ चुनाव होने पर राज्यपाल तटस्थ नहीं रह पाता, जबकि राज्यपाल को एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जो प्रांत को स्वीकार हो। उसे प्रांत के दले के तंत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सारी बातों के मद्देनजर यह बांधनीय होगा कि वह गन्ध के बाहर का व्यक्ति हो जो शिक्षा या किसी अन्य क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता हो जो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने में सरकार के साथ पूरा सहयोग करे। साथ ही, वह राजनीति से ऊपर दिखाई पड़े।

राज्यों का शासन

- क्या राज्यपाल को राष्ट्रपति की अपेक्षा विशिष्ट विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं? - हाँ
राज्यपाल विधानमंडल के ऊपरी सदन (विधान परिषद) के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? - 1/6 सदस्यों को
- राज्य विधानमंडल में एंग्लो-इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत उस समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? - एक सदस्य को
- राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्य के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व उससे परामर्श लिया जाता है। जिला एवं सत्र न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? - राज्यपाल
- राज्य के कानूनों के तहत दैडित अभियुक्तों को क्षमादान कौन दे सकता है, उनकी सजा को बदल सकता है या कम कर सकता है? - राज्यपाल
- राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होने के नाते कौन उपकुलपतियों की नियुक्ति करता है? - राज्यपाल
- आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसका निर्धारण समय-समय पर कौन करता है? - राष्ट्रपति
- राज्यपाल को अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी होना पड़ता है? - किसी भी न्यायालय के सम्मुख नहीं
- राज्यपाल के कार्यकाल में उसके विरुद्ध कोई भी फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता; लेकिन उसके विरुद्ध दोवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। इस मुकदमा के लिए कितने दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है? - दो महीने का
- क्या राज्यपाल की कार्यावधि के दौरान कोई भी न्यायालय उसे बंदी बनाने का आदेश दे सकता है? - नहीं
- 36वें संविधान संशोधन के द्वारा किस राज्य के राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गयी हैं, जिसके अनुसार सिक्किम के विभिन्न वर्गों के लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास का समान रूप से उचित प्रबंध करने और शांति की स्थापना करने के लिए राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होगी? - सिक्किम
- किस राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 371क के तहत राज्यपाल को कानून-व्यवस्था के बारे में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गयी है? - नगालैंड
- 55वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को जोड़कर इसमें अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को राज्य की अत्यंत नाजुक स्थिति के कारण कानून व व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जिसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में राज्यपाल मन्त्रिपरिषद में सलाह-मशाविरा करके की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपना व्यक्तिगत निर्णय ले सकेंगे? - अनुच्छेद 371एच
- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होने वाली किस अनुसूची के पैरा 20 में किये गये उल्लेख के अनुसार जिला परिषद और राज्य सरकार के बीच रॉयलटी के बटवारे से संबंधित मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करने के अधिकार दिये गये हैं? - छठी अनुसूची
- राज्यपाल विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। ऐसा वह प्रायः किसकी सलाह पर करता है? - मुख्यमंत्री
- प्रत्येक वर्ष विधानमंडल का अधिवेशन किसके भाषण से आरम्भ होता है, जिसमें राज्य की नीति का वर्णन होता है? - राज्यपाल
- यदि विधानमंडल के किसी सदस्य का अयोग्यता संबंधी कोई विवाद हो, तो उसका निर्णय राज्यपाल करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है, परंतु निर्णय देने से पूर्व राज्यपाल के लिए किस आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? - चुनाव आयोग
- प्रत्येक राज्यपाल अपने राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विफल हो जाने का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करता है, जिस पर वह संकटकाल की घोषणा करता है। इस दशा में मन्त्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। इस स्थिति में राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? - राष्ट्रपति

राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति

संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है। तात्पर्य यह कि वह स्वविवेक संबंधी कार्यों में मन्त्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। राज्यपाल को निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं-

- यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है।
- किसी दल को बहुमत सिद्ध करने हेतु कितना समय दिया जाना चाहिए यह भी राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है।
- आपातकाल के दौरान वह मन्त्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ऐसे समय में वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां और स्थिति की तुलना

- राष्ट्रपति का कार्यालय कार्यात्मक कम और औपचारिक अधिक होता है, लेकिन राज्यपाल का कार्यालय औपचारिक के साथ ही कार्यात्मक भी होता है।
- संविधान ने स्पष्टतः कुछ विशिष्ट विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल को प्रदान की हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए कोई सुस्पष्ट विवेकाधीन शक्तियां नहीं हैं।
- अनुच्छेद 163(2) के अनुसार, यदि किसी मुद्दे को लेकर यह प्रश्न उठे कि यह विवेकाधीन है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही इस दिशा में अंतिम होगा।
- अनुच्छेद 200 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर, राज्य विधायिका से परित अध्यादेश को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकता है। इस प्रकार की कोई शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है।
- अनुच्छेद 356 के अनुसार, राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य नहीं करने पर राष्ट्रपति को राज्य प्रशासन अधिग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है।

- राज्यपाल के को अभिकर्ता होता है, क्योंकि वह राज्य के मामलों को केंद्र को सूचित करता रहता है और इस विषय में वह किसको अपनी रिपोर्ट भेजता है? - **राष्ट्रपति**
- राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? - **राज्यपाल ही**
- राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? - **राज्य विधानमंडल**
- राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? - **छह सप्ताह**
- मुख्यमंत्री को नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी और विधानसभा को भंग करना राज्यपाल के विवेकाधिकार के अधीन आता है। राज्यपाल का यह अधिकार किस मामले में सीमित है? - **विधेयकों को स्वीकृति देना**
- राज्य विधानसभा को शक्ति किस पर निर्भर करती है? - **इसकी जनसंख्या पर**
- आपालकाल में राज्य विधानसभा को अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? - **संसद**
- संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा को सम्बोधित करने का प्रावधान है? - **अनुच्छेद 176**

मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्

- किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती, जिसका इधान मुख्यमंत्री होता? - **अनुच्छेद 163(1)**
- राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री को नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164(1) के तहत वह अन्य मंत्रियों को नियुक्ति किसको सलाह पर करता है? - **मुख्यमंत्री की सलाह पर**
- राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? - **मुख्यमंत्री**
- जन्मुकुरु: जो व्यवस्था केंद्र में अपनायी गयी है वही व्यवस्था राज्यों में भी अपनाई गयी है। अध्यारूप राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? - **राज्य की विधानसभा एवं राज्यपाल के प्रति**
- मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। उसका कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? - **विधानसभा के बहुमत के समर्थन पर**
- मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? - **विधानसभा**
- मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता है। संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री के परामर्श को माना जाना अधिकार न माना राज्यपाल पर निर्भर करता है, परंतु, व्यावहारिक रूप में क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्शों को मानने से इंकार कर सकता? - **सामान्यतः नहीं**
- या तो अधिक दून पड़ता है या फिर राज्यपाल को परामर्श देकर विधानसभा को भंग करके नये चुनाव कराने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र किसका त्यागपत्र भी माना जाता है? - **समस्त मंत्रिपरिषद का**
- मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के नियंत्रण राज्यपाल को और राज्यपाल के परामर्श को मंत्रिपरिषद तक नहीं होता है। व्यापराज्यपाल किसी विषय को मंत्रिपरिषद में विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकता है? - **हाँ**
- किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को दी गयी किसी सलाह को न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है? - **अनुच्छेद 163(3)**
- अनुच्छेद 163(3) के तहत क्या मंत्रियों को राज्यपाल के पास भेजे गये अधिनियमों का आदेशों पर हस्ताक्षर करने की वाध्यता है? - **नहीं**
- अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, किन राज्यों के राज्यपालों को यह दायित्व दिया गया है कि वे अपने राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करेंगे जो जाप ही अनुमूलिक जातियों और पिछड़े गए के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का खंड भारतीय हो सकेंगा? - **मध्य प्रदेश, छोटीसगढ़, झारखण्ड तथा ओडिशा**
(नोट: 95वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बिहार में यह पद समाप्त कर दिया गया है।)

- राज्यपाल का अस्तित्व मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना भी (राष्ट्रपति शासनकाल में) बना रह सकता है।
- **अनुच्छेद 371** कुछ विशेष राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व प्रदान करता है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर न्यायालय के निर्णय

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार
मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मार्च, 1994 को एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जो राज्यों में सरकारें भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करता है। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के फोन टैपिंग मामले में फंसने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया। इस फैसले में न्यायालय ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा।

रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार: इस मामले में वर्ष 2006 में दिये गये पांच सदस्यीय न्यायालयी ने निर्णय दिया कि यदि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे चुनाव पूर्व उन दलों में गठबंधन हो या न हो।

नवाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष: वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। अपनी कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए और यह सद्भावना के साथ की जानी चाहिए।

- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 164(1क) के तहत मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने प्रतिशत निर्धारित की गयी है? - **राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत**
 - जिन राज्यों को विधानसभाओं को सदस्य संख्या 60 या उससे कम है वहाँ कम से कम मुख्यमंत्री सहित कितने व्यक्ति मंत्री हो सकते हैं? - **12 व्यक्ति (अनुच्छेद 164-1क)**
 - अनुच्छेद 164(2) के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? - **राज्य विधानसभा के प्रति**
 - संविधान के अनुच्छेद 164 में उल्लेखित सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या तात्पर्य है?
 - मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे तथा किसी एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया, तो सरकार को त्वाग पत्र (इस्टीफा) देना होगा।
 - मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? - **राज्यपाल के प्रति**
 - यदि मंत्रिपरिषद कोई सदस्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो कितने दिनों के लिए मंत्री का पद धारण कर सकता है? - **6 माह के लिए**
 - किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य की सरकार को समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायेगी? - **अनुच्छेद 166(1)**
 - राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अधीन राज्य सरकार के काम को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए और उस काम को मंत्रियों में बांटने के लिए नियमों का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है? - **अनुच्छेद 166(3)**
 - किस संविधान संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी न्यायालय राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 166(3) के तहत बनाये गये नियमों को अपने सामने पेश करने को मांग नहीं कर सकता? - **42वा संविधान संशोधन**
 - किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वह राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद एवं विधानमंडल की कार्रवाइयों के बारे में सूचित करें? - **अनुच्छेद 167 में**
 - राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? - **मुख्यमंत्री**
 - किस अनुच्छेद के उपर्योगों के तहत यदि संसद विधानसभा की अवधि बढ़ा देती है, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी बढ़ सकता है? - **अनुच्छेद 172**
 - राज्य मंत्रियों के बेतन तथा भत्तों का निर्धारण कौन करता है? - **राज्य विधानमंडल**
- महाधिवक्ता**
- महाधिवक्ता राज्य सरकार का अधिकारी होता है एवं महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? - **अनुच्छेद 165**
 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। उसको नियुक्ति कौन करता है? - **राज्यपाल**
 - महाधिवक्ता राज्य सरकार को किस प्रकार को सलाह देता है? - **विधि संबंधी सलाह**
 - किस अनुच्छेद के अनुसार, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और इसके बेतन एवं भत्ते का निर्धारण भी राज्यपाल करता है? - **अनुच्छेद 165(3)**
 - भारतीय संविधान द्वारा इसके कार्यकाल का निर्धारण कितने वर्ष के लिए किया गया है? - **निश्चित नहीं है**
 - संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार, महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई के अधिकार के साथ राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में या उसकी समिति में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, परंतु क्या उस मत देने का अधिकार भी है? - **नहीं**
 - कौन-सी योग्यता प्राप्त किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता पद पर नियुक्त हो सकती है? - **उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता वाले व्यक्ति को**

राज्यपाल के संबंध में विभिन्न आयोगों व समितियों की सिफारिशें

प्रशासनिक सुधार आयोग (1966): वर्ष 1966 में केंद्र सरकार द्वारा नंगरजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) का गठन किया गया था। इसने यह सिफारिश की कि उस व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसे सार्वजनिक जोबन एवं प्रशासन का अनुभव हो और जो स्वयं को दलीय पूर्वांगों से मुक्त रखता हो। इसने यह भी कहा कि यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाये कि मंत्रिमंडल को विधानसभा का समर्थन प्राप्त नहीं रहा तो उसे विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री को कहना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री इस संबंध में आनंदानन्दी करता है तो राज्यपाल को स्वयं विधानसभा का सत्र बुलाकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।

भगवान सहाय समिति (1970): 1970 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल भगवान सहाय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। इसने सिफारिश की कि एसा व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य नहीं है या जिसे विधानसभा के लिए मनोनीत किया गया हो, वह मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना चाहिए न कि राज्यपाल के रूप में।

राजमन्त्र समिति (1969): 2 सितंबर, 1969 को तमिलनाडु के तत्कालीन डीएमके सरकार द्वारा केंद्र व राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए राजमन्त्र समिति का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1971 में प्रस्तुत की। इस समिति ने कहा कि विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल को विधानसभा का अधिकेशन बुलाना चाहिए और अधिकेशन में बहुमत से चुने गये व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए। समिति ने अनुच्छेद 356 और 357 को विलोपित करने की भी सिफारिश की।

सरकारिया आयोग (1983): जून 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने अक्टूबर 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजेव गाधी को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने कहा कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, राज्यपाल न तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और न उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है। राज्यपाल को किसी दूसरे राज्य से संबंधित होना चाहिए।

11

राज्य विधानमंडल एवं संघ राज्य क्षेत्र

विधानमंडल

- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद (यदि विधान परिषद हो तो) से मिलकर बनेगा? - अनुच्छेद 168
- वर्तमान में देश में 6 प्रांतों में दो सदनात्मक व्यवस्था स्थापित है। ये 6 प्रांत कौन-कौन से हैं? - उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना
- भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन- कौन सम्मिलित हैं? - राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद अगर अस्तित्व में हैं
- राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? - विधान परिषद

विधान परिषद

- अनुच्छेद 169(1) के अनुसार, संसद किसकी सहमति से राज्य विधान परिषद का सृजन अथवा उत्सादन (समाप्ति) कर सकती है?
 - राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम $\frac{2}{3}$ सदस्यों की सहमति से
- राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जिसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परंतु प्रत्येक दो वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? - एक तिहाई सदस्य
- अनुच्छेद 171(1) के अनुसार, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की कितनी हो सकती है? - $\frac{1}{3}$ से अधिक नहीं
- राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? - 40 सदस्य
- विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की एक-तिहाई एवं न्यूनतम संख्या 40 निश्चित की गयी है। सबसे नवोन्तम विधान परिषद कौन है? - तेलंगाना
- विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है?
 - अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा
- राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? - $\frac{1}{6}$ सदस्यों को
- विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के छठे भाग को राज्यपाल मनोनीत करता है। ये सदस्य किन क्षेत्रों के अनुभवी होते हैं?
 - साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता
- विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कौन-कौन सी योग्यता होना जरूरी है?
 - वह भारत का नागरिक हो एवं आयु 30 वर्ष से कम न हो
- विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उपरोक्त अर्हता (30 वर्ष की आयु एवं भारत का नागरिक होने की) के अलावा अन्य अर्हताएं किस अधिनियम के अंतर्गत दी गयी हैं?
 - जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951
- राज्य विधान परिषद के सदस्यों के बेतन एवं भत्ते का निर्धारण कौन करता है?
 - राज्य विधानमंडल
- विधान परिषद सदन के संचालन या अधिवेशन के लिए कितने सदस्यों की उपस्थितिअनिवार्य है? - सदन के कुल सदस्यों का $\frac{1}{10}$ वां भाग या कम से कम 10 सदस्य
- सदन के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिसमें सदन का अधिवेशन आरम्भ होने के 40 दिन पहले और अधिवेशन समाप्ति के 40 दिन बाद तक किन मामलों में बंदी या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है?
 - दीवानी मामलों में

राज्यों में विधानसभा की सीटें

क्रम	राज्य	सीटों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	403
2.	पश्चिम बंगाल	294
3.	महाराष्ट्र	288
4.	बिहार	243
5.	तमिलनाडु	234
6.	मध्य प्रदेश	230
7.	कर्नाटक	224
8.	राजस्थान	200
9.	गुजरात	182
10.	आंध्र प्रदेश	175
11.	ओडिशा	147
12.	केरल	140
13.	असम	126
14.	तेलंगाना	119
15.	पंजाब	117
16.	हरियाणा	90
17.	छत्तीसगढ़	90
18.	झारखण्ड	81
19.	उत्तरांचल	70
20.	हिमाचल प्रदेश	68
21.	त्रिपुरा	60
22.	नगालैंड	60
23.	मेघालय	60
24.	मणिपुर	60
25.	गोवा	40
26.	मिजोरम	40
27.	अरुणाचल प्रदेश	40
28.	सिक्किम	32
संघ राज्य क्षेत्र		83(107)
29.	जम्मू-कश्मीर	70
30.	दिल्ली	33
31.	पुडुचेरी	

नोट: केंद्रशासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के लिए 107 सदस्यों का प्रावधान है, लेकिन 24 स्थान राज्य के उन क्षेत्रों के लिए हैं, जो पाकिस्तान के क्षेत्राधिकार में हैं। पुडुचेरी के तीन विधानसभा सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किये जाते हैं।

राज्य विधानमंडल एवं संघ राज्य क्षेत्र

- विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति तथा एक उपसभापति निर्वाचित करती है, तथा इनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करके हटाया जा सकता है। परंतु यह प्रस्ताव पेश करने से पहले कितने दिनों की पूर्व सूचना देनी पड़ती है?

- 14 दिन से पूर्व सूचना

- विधान परिषद के सभापति का चुनाव सदन द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा के सभापति का चुनाव किसके द्वारा होता है?

- संसद के दोनों सदनों द्वारा

- विधान परिषद का सभापति कुछ परिस्थितियों में प्रथमतः वोट क्यों दे सकता है?

- क्योंकि वह सदन का सदस्य होता है

- विधान परिषद का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? - राज्यपाल द्वारा
- एक वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन होना आवश्यक है, परंतु एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच कितने महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए?

- 6 महीने से अधिक का अंतर

- विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकाधिक कितने दिन के लिए रोक सकती है?

- चार माह

- वित्तीय मामलों में विधान परिषद एक निर्बल सदन है। वह धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है?

- 14 दिनों तक

- धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, लेकिन किस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि उपाध्यक्ष भी धन विधेयक को प्रमाणित कर सकता है, किंतु वह ऐसा तभी करेगा जब अध्यक्ष का पद रिक्त है या अनुपस्थित हो?

- पंजाब बनाम सत्यपाल (1969)

- किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद, विधानसभा द्वारा पास किये गये विधेयक को अधिकतम कितने महीने तक रोक सकती है? - अधिकतम 4 महीने (दो बार में)

केंद्र (संघ) की तरह क्या राज्यों में साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है?

- नहीं

- किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुरस्थापित नहीं किया जायेगा?

- अनुच्छेद 198(1)

- भारतीय संविधान के अनुसार किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु उसको समाप्त किया जा सकता है?

- राज्य विधान परिषद

- भारत के किस प्रांत में विधान परिषद नहीं है, परंतु संविधान के सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 में उसके लिए उपबंध किया गया है? - मध्य प्रदेश

- भारत के किसी राज्य की विधान परिषद को कौन बना या समाप्त कर सकता है? - राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किये जाने के बाद संसद

विधानसभा

- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है?

- अनुच्छेद 170 में

- अनुच्छेद 170(1) के तहत किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इस सदन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? - 60

- भारत में 60 से भी कम सदस्यों वाली विधानसभा किन-किन राज्यों में है?

- गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम

- जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, वहां विधानसभा को क्या कहा जाता है?

- निम्न सदन

- राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?

- भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा

द्विसदनीय राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या

1. उत्तर प्रदेश	
• स्थानीय निकायों से निर्वाचित	37
• स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित	8
• शिक्षकों से निर्वाचित	8
• विधानसभा से निर्वाचित	38
• राज्यपाल द्वारा मनोनीत	10
• कुल सदस्य संख्या	100
2. महाराष्ट्र	
• स्थानीय निकायों से निर्वाचित	22
• स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित	7
• शिक्षकों से निर्वाचित	7
• विधानसभा से निर्वाचित	30
• राज्यपाल द्वारा मनोनीत	12
• कुल सदस्य संख्या	78
3. बिहार	
• स्थानीय निकायों से निर्वाचित	24
• स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित	6
• शिक्षकों से निर्वाचित	6
• विधानसभा से निर्वाचित	27
• राज्यपाल द्वारा मनोनीत	12
• कुल सदस्य संख्या	75
4. कर्नाटक	
• स्थानीय निकायों से निर्वाचित	25
• स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित	7
• शिक्षकों से निर्वाचित	7
• विधानसभा से निर्वाचित	25
• राज्यपाल द्वारा मनोनीत	11
• कुल सदस्य संख्या	75
5. तेलंगाना	
• स्थानीय निकायों से निर्वाचित	14
• स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित	3
• शिक्षकों से निर्वाचित	3
• विधानसभा से निर्वाचित	14
• राज्यपाल द्वारा मनोनीत	6
• कुल सदस्य संख्या	40

किरण NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को प्राप्त है? - अनुच्छेद 324 के तहत
- विधानसभा के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? - राज्य के राज्यपाल द्वारा
- विधानसभा के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है, परंतु ऐसे विनिश्चय से पूर्व राज्यपाल किसकी सलाह/राय लेता है? - निर्वाचन आयोग से है?
- राज्य सरकार के मंत्रियों के बेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत किसके द्वारा किया जाता है? - राज्य विधानसभा द्वारा
- संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? - राज्यपाल द्वारा
- भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य (कॉमन) सिविल कोड लागू है? - गोवा
- राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- भारत में वर्ष 1956 तक कितने पुर्णांगित राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिकाएं थीं? - पांच
- संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने का उपबंध किया गया है, इसलिए राज्यपाल अपने समस्त कृत्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करने के लिए बाध्य नहीं है? - अनुच्छेद 163 के अनुसार
- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विधेयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें? - अनुच्छेद 167 के तहत
- किस राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन् 1965 में 'सदर-ए-रियासत' से राज्यपाल में बदल दिया गया? - राज्य के संविधान के 6वें संशोधन द्वारा

किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या

अनुच्छेद 171(1) के मुताबिक विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं हो सकती। अनुच्छेद 171(3) के अंतर्गत विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव और मनोनयन का उल्लेख किया गया है। मनोनीत सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य अप्रत्यक्ष ढंग से चुने जाते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार हस्तांतरणीय मतदान द्वारा किया जाता है। ये सदस्य निम्न प्रकार चुने जाते हैं-

1. 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं-नगरपालिका, जिला परिषद के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा।
2. 1/12 सदस्य राज्य के उन निवासियों द्वारा चुने जाते हैं, जो भारत के किसी विश्वविद्यालय के स्नातक हों तथा कम से कम तीन वर्ष पहले स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण कर चुके हों।

यन विधेयक से भिन्न विधेयकों के संबंध में संसद तथा राज्य विधानमंडल की तुलना

संसद	राज्य विधानमंडल
<ol style="list-style-type: none"> 1. संसद के दोनों सदनों-राज्य सभा तथा लोकसभा में से किसी भी सदन में प्रारम्भ किया जा सकता है। 2. जब किसी ऐसे विधेयक को दोनों सदन उस विधेयक के मूल रूप में या संशोधनों सहित पारित कर देते हैं, तब वह संसद द्वारा पारित समझा जाता है। इस संबंध में विधेयक चाहे लोकसभा में प्रारम्भ हुआ हो अथवा राज्य सभा में, दूसरे सदन को उस पारित विधेयक पर समान अधिकार प्राप्त है। 3. एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन से छह माह के भीतर विधेयक पारित/या अस्वीकृत होकर आ जाना चाहिए। 4. एक सदन द्वारा पारित होने के पश्चात विधेयक यदि दूसरे सदन द्वारा (क) अस्वीकार कर दिया जाता है या (ख) ऐसे संशोधनों सहित प्रस्ताव करता है, जिनसे दूसरा सदन सहमत न हो, या (ग) विधेयक प्राप्ति के छह माह के भीतर पारित करके न भेजा जाये, तो दोनों सदनों में असहमति मानी जाती है। 5. असहमति होने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस संयुक्त अधिवेशन का निर्णय अंतिम होता है। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों-विधानसभा तथा विधान परिषद में से किसी भी सदन में प्रारम्भ किया जा सकता है। 2. यदि विधेयक विधान परिषद में पारित होता है, तो विधानसभा उस विधेयक को अस्वीकार कर दे या ऐसे संशोधन करे, जो कि विधान परिषद को स्वीकार नहीं हैं, तो वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। इस संबंध में विधानसभा तथा विधान परिषद को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। 3. विधानसभा में पारित विधेयक विधान परिषद में भेजा जाता है, जहां से उसे तीन मास के अंदर वापस आ जाना चाहिए। 4. विधानसभा द्वारा पारित विधेयक जब विधान परिषद को भेजा जाता है, तो विधान परिषद (क) विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, या (ख) विधेयक को ऐसे संशोधनों सहित पारित करती है, जिनसे विधानमंडल सहमत नहीं है, अथवा (ग) विधेयक की प्राप्ति के पश्चात तीन माह में वापस नहीं करती, तो दोनों सदनों में असहमति मानी जाती है। 5. असहमति होने पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी स्थिति में विधानसभा का निर्णय अंतिम होता है।

राज्य विधानमंडल एवं संघ राज्य क्षेत्र

- प्रांतों की विधानसभा किनके निर्वाचन में भाग लेती है?
 - राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में
- विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं?
 - लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं
- राष्ट्रीय आपात के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल खत्म होने के कितने समय बाद दोबारा निर्वाचन होना चाहिए?
 - छह माह के भीतर
- उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को 'गणपूर्ति' (कोरम) कहा जाता है, यह कितना होता है?
 - सदन में दस सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा

राज्य के विधानमंडल के अधिकारी

- विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गयी है?
 - अनुच्छेद 178 में
- किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपना पद रिक्त करना पड़ता है?
 - अनुच्छेद 179(क)
- किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा?
 - अनुच्छेद 179
- अनुच्छेद 179(ख) के मुताबिक राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है?
 - विधानसभा उपाध्यक्ष को
- विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अनुच्छेद 179(ग) के तहत विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के के किस बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है?
 - साधारण बहुमत से
- विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित संकल्प के प्रस्तावित करने के कितने दिन पूर्व की सूचना देना अनिवार्य है?
 - कम से कम 14 दिन
- विधानसभा अध्यक्ष सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है एवं स्वयंकार्यमंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामाज्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या धन विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है?
 - विधानसभा अध्यक्ष
- विधानसभा में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब इन दोनों के सदन में उपस्थित होने के बावजूद क्या अपने-अपने संबंधित संकल्पों में पीठासीन हो सकते हैं?
 - नहीं (अनुच्छेद 181-1)
- जब विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प सदन में विचाराधीन हो तब उसको बोलने, उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने और मत देने का अधिकार होता है। लेकिन ऐसे संकल्प पर उसको कब मत देने का अधिकार नहीं होता?
 - जब मत बराबर हो जाये
- अनुच्छेद 182 के अंतर्गत किसके चुनाव के संबंध में व्यवस्था की गयी है?
 - सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद
- विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने, पदत्याग करने और पद से हटाये जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?
 - अनुच्छेद 183
- अनुच्छेद 184 के मुताबिक जब विधान परिषद के सभापति का पद रिक्त हो तब उपसभापति और यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो सदन का कोई अन्य सदस्य उक्त पद के कर्तव्यों का पालन करता है। उस सदस्य की नियुक्ति कौन करता है?
 - राज्यपाल
- किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गयी है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति एवं उपसभापति के बीच भी आदि राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा निर्धारित होंगे?
 - अनुच्छेद 186 में

3. 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं, जो राज्य के हायर सेकंडरी स्कूलों या उसकी उच्च शिक्षा संस्थाओं अर्थात् कॉलेजों में कम से कम तीन वर्ष से पढ़ने का काम कर रहे हों।

4. 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा।

5. शेष 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है, जो राज्य के साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा में ख्याति प्राप्त कर चुके हों।

अनुपस्थित मतदान

अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र पर जाकर ही मतदान करना पड़ता है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो अनुपस्थित मतदान (Absentee Voting) का उपयोग करते हैं। इसमें डाक द्वारा मतदान में भाग या हिस्सा लिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यपाल, विदेशों में रह रहे राजदूत, उनकी पत्नियां एवं वयस्क बच्चे (यदि वे भारत के नागरिक हैं) सैनिक तथा निर्वाचन कार्य में लगे लोगों को अनुपस्थित मतदान अर्थात् डाक से मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है।

अभिभाषण

अभिभाषण से आशय राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण से है। चुनाव के तुरंत बाद संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्वारा या दोनों सदनों की प्रथम बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त सदन को सम्बोधित करना ही अभिभाषण कहलाता है। राज्यों में राज्यपाल भी चुनाव के तुरंत बाद या प्रथम वर्ष की संयुक्त बैठक के दौरान राज्य विधानमंडल में इसी तरह का अभिभाषण करता है।

प्रदत्त विधान

'प्रदत्त विधान' (Delegated Legislation) शब्द से आशय है- कानून बनाने की शक्ति किसी को देना। आधुनिक समय में विधायिकाओं के कार्य बढ़ गये हैं, फलतः सभी कार्यों का वह ठीक से सम्पादन नहीं कर पाती। ऐसे में वह अपने विधान बनाने

भाग-6, अध्याय-3

राज्य का विधानमंडल (The State Legislature)

(अनुच्छेद 168-212)

साधारण (General) (अनुच्छेद 168-177)

- अनुच्छेद 168: राज्यों के विधानमंडलों का गठन
- अनुच्छेद 169: राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
- अनुच्छेद 170: विधानसभाओं की संरचना
- अनुच्छेद 171: विधान परिषदों की संरचना
- अनुच्छेद 172: राज्यों के विधानमंडलों की अवधि
- अनुच्छेद 173: राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहंता
- अनुच्छेद 174: राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
- अनुच्छेद 175: सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको सदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
- अनुच्छेद 176: राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
- अनुच्छेद 177: सदनों के बारे में मत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

राज्य के विधानमंडल के अधिकारी (The Officers of the State Legislature) (अनुच्छेद 178-187)

- अनुच्छेद 178: विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 179: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 180: अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति
- अनुच्छेद 181: जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना
- अनुच्छेद 182: विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
- अनुच्छेद 183: सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 184: सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति
- अनुच्छेद 185: जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना
- अनुच्छेद 186: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 187: राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय

कार्य संचालन (Conduct of Business)

(अनुच्छेद 188-189)

- अनुच्छेद 188: सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 189: सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

सदस्यों की निरहताएं (Disqualifications of Members)

(अनुच्छेद 190-193)

- अनुच्छेद 190: स्थानों का रिक्त होना
- अनुच्छेद 191: सदस्यता के लिए निरहताएं

- अनुच्छेद 192: सदस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

- अनुच्छेद 193: अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने से पहले या अहिंत न होते हुए या निरहित किये जाने पर वेठने और मत देने के लिए शास्ति

राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

(Powers, Privileges and Immunities of State Legislatures and their Members) (अनुच्छेद 194-195)

- अनुच्छेद 194: विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि

- अनुच्छेद 195: सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

(अनुच्छेद 196-201)

- अनुच्छेद 196: विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किये जाने के संबंध में उपबंध

- अनुच्छेद 197: धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन

- अनुच्छेद 198: धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया

- अनुच्छेद 199: 'धन विधेयक' की परिभाषा

- अनुच्छेद 200: विधेयकों पर अनुमति

- अनुच्छेद 201: विचार के लिए आरक्षित विधेयक

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

(Procedure in Financial Matters) (अनुच्छेद 202-207)

- अनुच्छेद 202: वार्षिक वित्तीय विवरण

- अनुच्छेद 203: विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

- अनुच्छेद 204: विनियोग विधेयक

- अनुच्छेद 205: अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान

- अनुच्छेद 206: लेखानुदान, प्रत्यायानुदान और अपवादानुदान

- अनुच्छेद 207: वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

साधारणतया प्रक्रिया (Procedure Generally)

(अनुच्छेद 208-212)

- अनुच्छेद 208: प्रक्रिया के नियम

- अनुच्छेद 209: राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

- अनुच्छेद 210: विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

- अनुच्छेद 211: विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंधन

- अनुच्छेद 212: न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

अध्याय 4

राज्यपाल की विधायी शक्तियां

(Legislative Powers of the Governor)

- अनुच्छेद 213: विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति

राज्य विधानमंडल एवं संघ राज्य क्षेत्र

किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सचिवालय का प्रावधान किया गया है?

- अनुच्छेद 187 में

अनुच्छेद 187(2) के मुताबिक कौन राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तों का विनियमन करता है?

- राज्य विधानमंडल

जब तक राज्य विधानमंडल सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती एवं नियुक्ति की सेवा शर्तों संबंधी उपवंध नहीं करता तब तक अनुच्छेद 187(3) के तहत कौन विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति के परामर्श से संबंधित नियम बनाता है? - राज्यपाल

कार्य संचालन, सदस्यों की निरहंताएं और शक्तियां

■ राज्य विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है?

- अनुच्छेद 188

■ विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य को राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता या प्रतिज्ञान करता है। इस प्रयोजन के लिए प्रारूप संविधान के किस भाग में दिया गया है?

- तीसरी अनुसूची में

■ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों के अवधारण के दौरान अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णयक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? - अनुच्छेद 189(1)

■ अनुच्छेद 189(3) के मुताबिक किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन चलाने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? - 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, इसमें से जो भी अधिक हो

■ किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं होने पर अध्यक्ष या सभापति या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का किस अनुच्छेद के तहत यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है? - अनुच्छेद 189(4)

■ अनुच्छेद 190(1) के मुताबिक कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो होगा। किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं होगा? - अनुच्छेद 190(2)

■ किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य कितने दिनों की अवधि तक सदन को अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा? - 60 दिन

■ यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरहित न होना राज्य के विधानमंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है तो क्या उसकी सदस्यता चली जाती है? - हां (अनुच्छेद 190-क)

■ यदि कोई व्यक्ति अनुन्मोचित दिवालिया (Undischarged Insolvent) हो तो क्या वह विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बन सकता है? - नहीं (अनुच्छेद 190-ग)

■ किस अनुसूची के अधीन निरहित होने पर कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने के योग्य नहीं रह जाता? - दसवीं अनुसूची

■ किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य यदि अनुच्छेद 191(1) के तहत निरहित हो जाता है तो इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है? - राज्यपाल

■ विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य की निरहता के प्रश्न विनिश्चय करने से पूर्व राज्यपाल किससे सलाह करता है? - निर्वाचन आयोग

की शक्ति को कार्यपालिका या किसी सक्षम प्राधिकारी को सौंप सकती है। इसे प्रदत्त विधान इसलिए कहते हैं, क्योंकि शक्ति दी जाती है, प्रदत्त की जाती है। इसमें मूल सत्ता की शक्ति में हास नहीं होता है।

अविश्वास प्रस्ताव

संसदीय शासन में मंत्रिपरिषद तभी तक पदासीन रहती है, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन हो। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका से असंतुष्ट है, तो वह उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) ला सकती है। इस प्रस्ताव पर लोकसभा के 1/10 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किये जाने के बाद यदि लोकसभा का बहुमत इसे स्वीकार करता है, तो कार्यपालिका बख़स्त हो जाती है। वास्तव में, यह कार्यपालिका के नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका उल्लेख लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 198 में किया गया है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1962 में किया गया था।

निंदा प्रस्ताव

'निंदा प्रस्ताव' (Censure Motion) का उल्लेख प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 184 से 189 तक में किया गया है। निंदा प्रस्ताव में निंदा का कारण बताना जरूरी है। यदि लोकसभा अध्यक्ष यह समझता है कि प्रस्ताव निंदा करने लायक है, तो वह इसे स्वीकृति दे सकता है। इस प्रस्ताव द्वारा सदन के सदस्य किसी मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के किसी कार्य की निंदा करते हैं। इसमें सदस्यों द्वारा रोष व्यक्त किया जाता है तथा उसकी विफलता को निंदा का आधार बनाया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य कार्यपालिका को सजग करना भी है। यह एक साधारण प्रस्ताव है।

कटौती प्रस्ताव

यह ऐसा प्रस्ताव है, जिसके द्वारा सदन के सदस्य सरकार के किसी विभाग की धनराशि में कटौती की मांग करते हैं। कटौती प्रस्ताव (Cut Motion) के तीन प्रकार हैं: (अ) नीतिगत कटौती: इसमें सरकार के सिद्धांतों या नीतियों से असहमति व्यक्त की जाती है;

किरण NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पूर्व अथवा अहिंत न होते हुए या निरहित किये जाने पर किसी व्यक्ति/सदस्य को किसी सदन के अधिवेशन में बैठने और मत देने का दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी शास्ति (चम्दंसजल) देनी पड़ती है? - प्रतिदिन 500 रुपये की शास्ति
- क्या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में दिये गये भाषण के लिए सदस्यों के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा चलाया जा सकता है? - नहीं [अनुच्छेद 194 (2)]
- विधानमंडल के किसी सदस्य को सदन का अधिवेशन आरम्भ होने से कितने दिन पहले और अधिवेशन समाप्त होने के कितने दिन बाद तक के बीच के समय में दोनों मुकदमों के लिए बन्दी नहीं बनाया जा सकता है? - 40-40 दिन
- कौन अनुच्छेद 195 के तहत अपने कानून द्वारा विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते निश्चित करता है? - प्रांत का विधानमंडल
- क्या सभी राज्यों में विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते इत्यादि समान होते हैं? - नहीं

(नोट: वेतन-भत्ते इसलिए समान नहीं होते, क्योंकि सभी राज्य विधानमंडल वेतन-भत्तों का निर्धारण अलग-अलग करते हैं इसलिए इनका समान होना स्वाभाविक नहीं होता।)

विधायी प्रक्रिया

- किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण भी बतायेगा? - अनुच्छेद 176(1)
- किस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक, धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, द्विसदनीय विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा? - अनुच्छेद 196
- किस अनुच्छेद के तहत किसी द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य में कोई विधेयक तब तक पारित नहीं माना जायेगा जब तक कि वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित नहीं कर दिया जाता? - अनुच्छेद 196(2)
- किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत (Lapse) नहीं होता, लेकिन क्या किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक, जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है, विधानसभा के विघटन पर व्यपगत होता है? - नहीं
- कोई विधेयक, जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है या जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में लंबित है, विधानसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है? - हाँ
- अनुच्छेद 198 के तहत धन विधेयक कहां प्रस्तुत/पुरुःस्थापित किया जा सकता है? - सिर्फ विधानसभा में (विधान परिषद में नहीं)
- धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गयी है? - अनुच्छेद 199
- अनुच्छेद 200 के तहत किस विधेयक के मामले में राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजे? - धन विधेयक
- किस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? - अनुच्छेद 200
- राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित करता है? - अनुच्छेद 201

(ब) अर्थात् कटौती: किसी खास मद में मांगी गयी राशि में कुछ कटौती से ऐसा प्रस्ताव संबंधित होता है, एवं

(स) सांकेतिक या प्रतीक कटौती: इस प्रस्ताव में सरकार की किसी मद में मांगी गयी राशि का विरोध किया जाता है। विरोध करने का तरीका यह है कि मांगी गयी राशि में संकेत के रूप में 100 रुपये की कटौती की मांग की जाती है।

आधे घटे की चर्चा

यह प्रस्ताव ऐसे प्रश्न पर उत्पन्न होता है, जिसका उत्तर सदन में पहले ही दिया जा चुका है। आधे घटे की चर्चा का संबंध भी लोक महत्व के प्रश्न से होता है। कार्य संचालन नियम की धारा 55 में इसका उल्लेख है। यह चर्चा सदन की समाप्ति से ठीक आधे घटे पहले शुरू की जाती है। यदि इस प्रस्ताव की सूचना लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति के कम-से-कम तीन दिन पूर्व देनी पड़ती है।

अल्पकालीन चर्चाएं

ये चर्चाएं संसद के दोनों सदनों में उठायी जाती हैं। अल्पकालीन चर्चाओं का संबंध भी अविलम्बनीय कार्य एवं प्रक्रिया संचालन अधिनियम 193 में किया गया है। ऐसी चर्चा की सूचना दो सदस्यों के समर्थन से महासचिव को दी जाती है। उसके बाद अध्यक्ष की स्वीकृति से यह चर्चा की जाती है। यदि अध्यक्ष इंकार करे, तो प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह सदन की बैठक की समाप्ति से आधे या एक घटे पहले शुरू की जा सकती है। इस प्रस्ताव के उत्तर में मंत्री को उत्तर देना पड़ता है।

अल्प सूचना प्रश्न

अल्प सूचना प्रश्न अति महत्व के प्रश्न होते हैं। इनका संबंध प्रायः सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों से होता है। यह प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष को 10 दिन से कम अवधि की सूचना देकर पूछने की अनुमति मांगी जाती है। यदि अध्यक्ष समझता है कि प्रश्न लोक सभा का है, तो वह इसे पूछने की इजाजत दे सकता है। प्रश्न काल की समाप्ति के बाद किसी निर्धारित दिन यह प्रश्न किया जा सकता है।

राज्य विधानमंडल एवं संघ राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद 202 के प्रावधान के मुताबिक राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्रावकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाता है। इसको क्या कहा जाता है?

- वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

राज्य में किसी अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर की जाती है? - राज्यपाल विनियोग विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 204 में तथा अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान का प्रावधान अनुच्छेद 205 में किया गया है। लेखानुदान, प्रत्यायानुदान और अपवादानुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? - अनुच्छेद 206 में जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किये जाने पर राज्य की संचित निधि में से व्यय करना पड़े उस विधेयक को किसकी अनुमति के बिना विधानमंडल के किसी भी सदन में पारित नहीं किया जा सकता? - राज्यपाल [अनुच्छेद 207(3)]

द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य में राज्यपाल किससे परामर्श करने के बाद दोनों सदनों में परस्पर संचार संबंधी प्रक्रिया के नियम बना सकते?

- अध्यक्ष, विधानसभा और सभापति, विधान परिषद

राज्य विधायिका में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर कोई बहस नहीं हो सकती है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है?

- अनुच्छेद 211

क्या किसी न्यायालय द्वारा राज्य के विधानमंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अधिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत किया जा सकता है? - नहीं [अनुच्छेद 212(1)]

विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश (Ordinance) प्रख्यापित करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? - अनुच्छेद 213

किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों को राज्य की जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा? - अनुच्छेद 332

अनुच्छेद 333 के तहत किसके पास यह विशेष शक्ति है कि वह राज्य की विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक सदस्य को शामिल करे? - राज्यपाल

विधानसभा को किस सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए विधेयक पास करने का अधिकार होता है? - राज्य सूची और समवर्ती सूची

राज्य के वित्त पर विधानसभा का ही नियंत्रण होता है या विधान परिषद का? - विधानसभा का

(नोट: धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं। राज्य का वार्षिक बजट भी इसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार न कोई कर लगा सकती है और न ही कोई पैसा खर्च कर सकती है।) विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं?

- एक तिहाई सदस्यों का

विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। क्या यह अधिकार विधान परिषद को भी प्राप्त है? - नहीं

राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों में बढ़ोतरी कौन कर सकता है? - विधानमंडल किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मत्रियों की सलाह की बाध्यता तय की गयी है, परंतु राज्यपाल के लिए नहीं? - 42वां संविधान संशोधन (1976)

प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है। वह किसके माध्यम से इसके प्रशासन का संचालन करते हैं?

- लेपिटेंट गवर्नर, प्रशासक या अन्य कोई पदनाम

अध्यावेश

जब संसद या राज्य विधानमंडल सत्र में न हो एवं कई आवश्यक समस्या उत्पन्न हो जाये, तो इससे निपटने के लिए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को क्रमशः धारा 123 एवं 213 के अंतर्गत अध्यादेश (Ordinance) जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश का वही महत्व है, जो संसद द्वारा निर्मित कानूनों को प्राप्त है। यदि संसद या राज्य विधानमंडल के निम्न सदन इसे अपनी प्रथम वैठक में स्वीकृति नहीं देते, तो वैठक की तारीख से 6 सप्ताह बाद अध्यादेश स्वतः खत्म हो जाता है।

बाई-कैमरलिज्म

बाई-कैमरलिज्म (Bi-Cameralism) से आशय द्विसदनात्मक पद्धति से है। जहां कहीं भी विधायिका के दो सदन हैं, वहां यह व्यवस्था बाई-कैमरलिज्म कही जाती है।

अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान की मांगें

संसद की स्वीकृति के बिना उसके द्वारा स्वीकृति राशि से अधिक राशि खर्च नहीं की जा सकती है। परंतु, यदि किसी प्रयोजन के लिए कोई राशि कम पड़े जाती है, तो राष्ट्रपति उसके पूरक राशि के रूप में 'अनुपूरक राशि' को दोनों सदनों में रखवाता है। इसे अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grants) कहते हैं। जब किसी निर्धारित राशि से अधिक राशि किसी मत में खर्च हो जाती है, तो राष्ट्रपति इस खर्च की पूर्ति के लिए 'अतिरिक्त राशि' की मांग दोनों सदनों में रखवाता है। इसे 'अतिरिक्त अनुदान' (Excess Demand for Grants) कहते हैं। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 115 में की गयी है।

प्रत्यायानुदान एवं अपवादानुदान

प्रत्यायानुदान (Vote of Credit Grant) तब लिया जाता है, जब संकट की स्थिति एकाएक उत्पन्न हो जाये एवं धन की कमी हो जाये। ऐसे में, कार्यपालिका अर्थात् सरकार को धन की स्वीकृति संसद से लेनी पड़ती है, जो संसद तुरंत दे देती है। वह प्रत्यायानुदान के समय धन का ब्यौरा नहीं

किंवित NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संसद द्वारा निर्मित विधियों के अलावा किसके द्वारा निर्मित विधियों के अनुसार संचालित करता है?
 - **संघ राज्य क्षेत्र में मौजूद विधानसभा द्वारा**
- केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक किसका एजेंट या अधिकारी होता है न कि राज्यपाल की भाँति राज्य प्रमुख?
 - **राष्ट्रपति**
- संघ राज्य क्षेत्र में यदि विधानसभा का विघटन हो गया हो या विधानसभा निलम्बित हो गयी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकता है? - **नहीं**
- भारत के मूल संविधान में संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था नहीं थी। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 339ए जोड़कर संसद को यह शक्ति प्रदान की गयी कि वह विधि बनाकर संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद स्थापित कर सकती है? - **14वें संविधान संशोधन (1962) द्वारा**
- संसद जब किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद से संबंधित कानून बनाती है, तो उस विधि में यह भी उल्लेख रहता है कि विधानसभा राज्य सूची के किन नियमों पर कानून बना सकती है। क्या यह कथन सत्य है? - **हां**
- पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए संसद ने किस अनुच्छेद के अधीन पुडुचेरी (प्रशासन) अधिनियम, 1962 अधिनियमित करके विधानमंडल आदि के लिए उपबंध किया है?
 - **अनुच्छेद 239क**
- 1992 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन-से दो नये अनुच्छेद अंतःस्थापित किये गये, जिनके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए मंत्रिमंडल का उपबंध किया गया?
 - **अनुच्छेद 239कक और 239कछ**
- दिल्ली शासन को राज्य सूची की समस्त विधायी शक्तियां प्राप्त हैं केवल तीन को छोड़कर। ये तीन प्रविष्टियां कौन-सी हैं? - **लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि**
- संसद को संघ राज्य क्षेत्र पर अनन्य विधायी शक्ति प्राप्त है। इसमें वे विषय भी शामिल हैं जो राज्य सूची में आते हैं [अनुच्छेद 246(4)]; किंतु किन दो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति को विधायी शक्ति है? - **दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव और पुडुचेरी**

पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं की शक्तियों में अंतर

संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 239ए और 239एए के तहत पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं की शक्तियों में अंतर विद्यमान है। सामान्यतः दिल्ली और पुडुचेरी दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में निर्वाचित सरकारें हैं, किंतु इसके बावजूद इन प्रदेशों के उपराज्यपालों की शक्तियों में कुछ अंतर पाया जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पुडुचेरी के उपराज्यपाल से अधिक शक्तियां हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल को कार्यकारी शक्तियों के साथ-साथ कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र, पुलिस एवं भूमि से जुड़े मामलों में देखा जा सकता है। वह अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिये गये किसी आदेश को उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से लागू भी कर सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 और दिल्ली एनसीटी सरकार कामकाज नियम, 1993 के तहत तथा पुडुचेरी के उपराज्यपाल को केवल केंद्रशासित प्रदेशों के सरकार संबंधी अधिनियम 1963 द्वारा निर्देशित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239ए और 239एए के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में यह स्पष्ट उत्तिलिखित है कि केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में संघ सरकार की भूमिका संविधान में भी दिल्ली सरकार को आंख और कान की भूमिका निभाता है। सभी अधिकार प्राप्त हैं, जबकि पुडुचेरी विधानसभा समवर्ती और राज्य सूची के तहत किसी अंतर्विरोध की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून को ही प्राथमिकता दी जाये। पुडुचेरी में 1963 के व्यापार संबंधी नियमों में वर्णित कार्यों को निर्वाचित सरकार (मंत्रिपरिषद) देखती है और वैसी ही शक्तियां वहां के उपराज्यपाल को भी प्राप्त हैं।

मांगती। अपवादानुदान (*Vote of Exemption Grant*) किसी विशिष्ट ध्येय की पूर्ति के लिए दिया जाता है। यह वित्तीय वर्ष के खर्च का भाग नहीं होता है। अनुच्छेद 116 में इनकी चर्चा की गयी है।

संघ राज्य क्षेत्र (The Union Territories)

- **अनुच्छेद 239:** संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन।
- **अनुच्छेद 239क:** कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सूजन।
- **अनुच्छेद 239कक:** दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध।
- **अनुच्छेद 239कछ:** संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध।
- **अनुच्छेद 239ख:** विधानमंडलों का विश्रातिकाल में अध्यादेश जारी करने की प्रशासक की शक्ति।
- **अनुच्छेद 240:** कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
- **अनुच्छेद 241:** संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय।
- **अनुच्छेद 242:** (निरसित)

अर्जित राज्यक्षेत्र

संविधान में अर्जित राज्यक्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में पृथक् उपबंध नहीं हैं, किंतु अनुच्छेद 366(30) में यह व्यवस्था की गयी है कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत के राज्यक्षेत्र में कोई ऐसा अन्य राज्यक्षेत्र भी शामिल होगा जो भारत के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट है अर्थात् जिसे भारत द्वारा अर्जित किया गया है लेकिन जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। इस प्रकार अर्जित किये गये राज्यक्षेत्र का अनुच्छेद 246(4) के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के विधान के अधीन प्रशासन चलाया जायेगा। उदाहरणार्थ, 1962 तक पुडुचेरी, करायकल, यानम और माहे का प्रशासन अर्जित राज्यक्षेत्र के रूप में चलाया जाता था, लेकिन 1962 में इन्हें सम्मिलित रूप से 'पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र' का दर्जा दे दिया गया।

पंचायती राज

- किस वॉयसराय को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है? - लॉर्ड रिपन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया। इसे भारतीय स्वशासन के इतिहास में क्या कहा जाता है? - मैग्नाकार्टा
- सन् 1909 में किस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह संस्तुति की कि 'ग्राम' को स्थानीय स्वशासन की बुनियादी इकाई माना जाये तथा प्रत्येक ग्राम में पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकाओं का गठन किया जाये? - रॉयल विकेंट्रीकरण आयोग
- 1919 के भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखा गया था। इसमें कानून बनाने की शक्ति किसके पास थी? - प्रांतीय विधायिकाओं के पास
- गांवों के लिए न्याय पंचायत गठित करने की सिफारिश किस समिति ने की? - एल.एम. सिंघवी समिति
- 2 अक्टूबर, 1959 को देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन कहां किया गया? - नागौर जिला, राजस्थान
- नागौर के बाद किस तिथि को पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के शाद नगर विकासखंड में शुरू की गयी? - 11 अक्टूबर, 1959 को
- भारत में पंचायती राज प्रणाली का विधिवत प्रारम्भ किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया? - बलवंतराय मेहता समिति
- पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? - अनुच्छेद 40
- 1952 में पं. जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया। इन कार्यक्रमों की विफलता की जांच के लिए बलवंतराय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? - वर्ष 1956 में
- बलवंतराय समिति ने पंचायत राज व्यवस्था के लिए तीन स्तरीय ढांचा का सुझाव दिया। ये तीन स्तर कौन-से हैं? - ग्राम स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत या क्षेत्रीय समिति, तथा जिला स्तर पर जिला परिषद
- तमिलनाडु और कर्नाटक में जिला परिषद के स्थान पर क्या होता था? - जिला विकास परिषद
- मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा में द्वि-स्तरीय प्रणाली (ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां) लागू की गयी थीं। किस राज्य में चार स्तरीय प्रणाली (ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद तथा जिला परिषद) विद्यमान थी? - पश्चिम बंगाल
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद अब प्रत्येक राज्य में पंचायत के कितने स्तर मौजूद हैं? - तीन स्तर
- भारतीय राज्यों में से त्रि-स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? - राजस्थान
- भारत में पृथक् पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? - वर्ष 2004

पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद

- अनुच्छेद 243: परिभाषा।
- अनुच्छेद 243क: ग्रामसभा।
- अनुच्छेद 243ख: ग्राम पंचायतों का गठन।
- अनुच्छेद 243ग: पंचायतों की संरचना।
- अनुच्छेद 243घ: स्थानों का आरक्षण।
- अनुच्छेद 243इ: पंचायतों की अवधि।
- अनुच्छेद 243च: सदस्यता के लिए अयोग्यताएं।
- अनुच्छेद 243छ: पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।
- अनुच्छेद 243ज: पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां व निधियां।
- अनुच्छेद 243झ: वित्त आयोग।
- अनुच्छेद 243ञ: पंचायतों की लेखाएं।
- अनुच्छेद 243ट: पंचायतों के लिए निर्वाचन।
- अनुच्छेद 243ठ: संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना।
- अनुच्छेद 243ड: इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना।
- अनुच्छेद 243ढ़: विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना।
- अनुच्छेद 243ण: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन।

पंचायती राज व्यवस्था: कालानुक्रम

- 1864: भारत सरकार का प्रस्ताव, जिसमें स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत को मान्यता।
- 1870: लॉर्ड मेयो - पंचायतों को कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता।
- 1882: लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव, जिसे स्थानीय शासन का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है।

किरण NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड में बुनियादी स्तर पर प्रशासनिक इकाई के रूप में कौन-सी परिषदें कार्यरत हैं? - **जनजातीय परिषदें**
- किस राज्य में जहां ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं, अनुच्छेद 243(1) के तहत पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान लागू नहीं होते? - **मणिपुर**
- पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में भी अनुच्छेद 243(1) के प्रावधान लागू नहीं होते। यहां कौन-सी परिषद विद्यमान है?

- दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद

- प्रचलित पंचायती राजव्यवस्था का अध्ययन करने और सुधार का सुझाव देने के लिए दिसंबर 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कितने स्तरों की पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की? - **द्वि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था**
- 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक व्यवस्था हेतु गठित किस समिति ने अपनी सुझावों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन एवं निरीक्षण के संदर्भ में जिला एवं उसके नीचे के स्तरों के पंचायती राज संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया?
- **जी.वी.के. राव समिति**
- 1986 में गठित किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक पहचान देने, ग्राम समूह के लिए एक न्याय पंचायत की व्यवस्था करने, ग्राम पंचायत के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने तथा पंचायती राज चुनाव के विवादों से निपटने के लिए राज्य में एक न्यायाधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की? - **एल.एम. सिंधवी समिति**
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक अर्थों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं बनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्ष 1988 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिये जाने की सिफारिश की?
- **पी.के. थुंगन**

(नोट: पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए 1989 में 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिया गया। इसके बाद लोकसभा को भंग कर दिये जाने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया।)

- थुंगन समिति की ही सिफारिश पर मई 1989 में स्थानीय स्वशासन के लिए 64वां व 65वां संविधान संशोधन लोकसभा में पारित हो गया, किंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। किसकी सरकार ने राजीव गांधी के इस सपने को पूरा किया?

- नरसिंहा राव सरकार

- 20 अप्रैल, 1993 को पंचायती राज व्यवस्था संबंधी विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गयी तथा इन्हें 73वां व 74वां संविधान संशोधन क्रमांक दिये गये। ये दोनों विधेयक कब अधिनियम बने?
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 को पूरे देश में 24 अप्रैल, 1993 को लागू किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 को कब लागू किया गया?
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को पूरे देश में लागू करने के दिवस (24 अप्रैल) को प्रतिवर्ष किस नाम से मनाया जाता है? - **1 जून, 1993 को**

- 23 अप्रैल, 1993 को

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को पूरे देश में लागू करने के दिवस (24 अप्रैल) को प्रतिवर्ष किस नाम से मनाया जाता है? - **राष्ट्रीय पंचायत दिवस**
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार 1996 अधिनियम) विधेयक किस समिति की सिफारिशों पर पेश किया गया?

- भूरिया समिति

- 1909: विकेन्द्रीकरण पर रॉयल कमीशन का प्रतिवेदन (1907 में कमीशन का गठन)।
- 1951: स्थानीय वित्त जांच समिति (पी.के. बटल)।
- 1952: सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत।
- 1957: बलवंतराय मेहता समिति ने राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रतिवेदन सुपुर्द किया।
- 1959: नागौर में पंचायती राज एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरुआत।
- 1961: पंचायत एवं सहकारिता पर कार्यसमूह (एस.डी. मिश्र)।
- 1961: पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल (वी. ईश्वरन)।
- 1962: न्याय पंचायत पर अध्ययन दल (जी.आर. राजगोपाल)।
- 1963: पंचायती राज आंदोलन में ग्रामसभा की स्थिति पर अध्ययन दल (आर.आर. दिवाकर)।
- 1963: पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल (के. संथानम), पंचायती राज निवाचनों पर अध्ययन दल (के. संथानम), 1965 पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षण एवं लेखांकन पर अध्ययन दल (आर.के. खना)।
- 1966: पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों पर अध्ययन दल (जी. रामचंद्रन)।
- 1976: सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज अध्ययन समिति (श्रीमती दया चौबे)।
- 1977: पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की नियुक्ति।
- 1978: अशोक मेहता समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
- 1985: ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवाचन कार्यक्रमों के प्रशासनिक प्रबंधीकरण पर समिति (जी.वी.के. राव)।
- 1985: कर्नाटक में पंचायती राज का पुनरुत्थान।

स्थानीय शासन

- 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन-सा नया भाग शामिल करते हुए इसे 'पंचायत' नाम दिया गया? - भाग-IX
- 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी। पंचायती राज किन अनुच्छेदों से संबंधित है? - 243 से 243ण
- पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। कार्यकाल खत्म होने की तिथि के छह माह पूर्व ही नया चुनाव होना चाहिए। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? - 21 वर्ष
- पंचायती राज कानून जम्मू-कश्मीर, नगालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, लेकिन संसद चाहे तो कानून का विस्तार कर सकती है। इस कड़ी में कौन-सा कानून बनाया गया?
- - पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1996
- संविधान में भाग 9, अनुच्छेद 243, 243(क) से 243(ण) तक जोड़े गये। पंचायत राज व्यवस्था संबंधी अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? - मात्र 16
- संविधान में जोड़ी गयी ग्यारहवीं अनुसूची में कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, लघु सिंचाई और शिक्षा जैसे पंचायतों के कितने कार्यों का उल्लेख है? - 29 कार्यों का
- किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि यह सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों को पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किये जायें? - अनुच्छेद 243(क)
- अनुच्छेद 243(ख) में पंचायत के तीन स्तरों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर) और जिला परिषद का उल्लेख है। कितनी आवादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पंचायत का गठन करना आवश्यक नहीं है? - 20 लाख से कम
- प्रत्येक पंचायत का चुनाव कितनी अवधि के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है? - पांच वर्ष
- किस अनुच्छेद के अनुसार, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अनुसार भिन्न-भिन्न स्तरों पर सदस्य होंगे? - अनुच्छेद 243ग
- पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव संबंधी विधि का फैसला कौन करता है? - राज्य विधानमंडल
- प्रत्येक पंचायत स्तर में कुल सदस्य संख्या का कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी शामिल है? - एक-तिहाई
- किस अनुच्छेद के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे?
- - अनुच्छेद 243घ (1)
- किस अनुच्छेद में पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षणीय व्यवस्था की गयी है? - अनुच्छेद 243घ (4)
- अनुच्छेद 243ज के अनुसार, किन संस्थाओं को अपनी सीमा में कर, शुल्क, पथ कर और शुल्क अधिरोपित, संग्रहित व विनियोजित करने की शक्ति प्राप्त है? - पंचायतों को
- अनुच्छेद 243 झ के तहत राज्यपाल संशोधन लागू होने के एक वर्ष के भीतर व उसके पश्चात प्रत्येक पांच वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु किस आयोग का गठन करता है? - वित्त आयोग

- 1986: लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन हेतु लक्ष्मीमल सिंघवी का प्रतिवेदन।
- 1992: 73वां संविधान संशोधन।
- 1993: राष्ट्रपति द्वारा 73वें संशोधन की स्वीकृति।

पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां, वर्ष एवं अनुशंसाएं

- बलवंतराय मेहता समिति (1956)- त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा।
- अशोक मेहता समिति (1977)- द्विस्तरीय संरचना का प्रस्ताव।
- जी.के.वी. राव समिति (1985)- पंचायती राज को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देने के लिए।
- एल.एम. सिंघवी समिति (1987)- पंचायती राज को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देने के लिए।
- वी.एन. गाडगिल समिति (1989)- त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के प्रारूप को प्रस्तुत किया।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण क्या है?

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक प्रकार की शासन प्रणाली है, जहां साधारणतया शक्ति केन्द्र से परिधि की ओर जाती है, उदाहरण के लिए केन्द्र से ताकत राज्यों को और राज्यों से जिलों को जाती है। इस प्रणाली में स्थानीय संस्थाओं को ही शक्ति पुंज बनाया जाता है ताकि वे अपनी जरूरतों के मुताबिक फैसले ले सकें और उन्हें अमलीजामा पहना सकें। इस प्रकार सत्ता का हस्तांतरण सरकार के ऊंचे स्तर से निचले स्तर को किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह प्रक्रिया लम्बवत (Vertical) होती है न कि क्षैतिजीय (Horizontal)। भारत में पंचायती राज संस्थाओं ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आदर्श को एक ठोस संस्थात्मक आधार प्रदान किया है।

किंतु NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

■ चुनावी प्रक्रिया की तैयारी, देख-रेख, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों को सम्पन्न कराने की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। इसके लिए अनुच्छेद 243ट के तहत एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?

- राज्यपाल

■ पंचायतों का मनमाने तरीके से विघटन नहीं किया जा सकता। विघटन की स्थिति में कितनी अवधि के पूर्व चुनाव करवाना जरूरी है?

- 6 माह के पूर्व

■ यदि चुनावों के 6 माह के बाद पंचायत विघटित की जाती है, तो अनुच्छेद 243ट(4) के मुताबिक अगला चुनाव कितने काल के लिए होगा? - शेष बचे काल के लिए

■ पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास में जन-भागीदारी और राजनीतिक जवाबदेही के अलावा क्या सुनिश्चित करना है? - लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

■ विहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि पांच वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कैसे होती है? - पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है

■ ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जायेगा?

- सात दिनों बाद

■ मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। विहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा?

- जिला पंचायती राज पदाधिकारी

■ विहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 में दो ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है?

- तीन महीने

■ ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप-मुखिया का चुनाव करते हैं। उप-मुखिया के निर्वाचन में कौन मतदाता नहीं होता?

- मुखिया

■ पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है?

- जिला परिषदें

■ स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहान प्रावधान कहां लागू किया गया था?

- मध्य प्रदेश

■ अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए?

- सात

■ पंचायती राज की संरचना है?

- जिला पंचायत-ब्लॉक पंचायत-ग्राम पंचायत-ग्राम सभा

■ विहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है?

- पंचायत समिति के प्रमुख

■ त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है?

- जिला परिषद

■ ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन करवाता है?

- राज्य चुनाव आयोग

■ भारत पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है?

- सत्ता का विकेन्द्रीकरण

■ ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें किसके द्वारा आद्वान की जाती हैं?

- ग्राम पंचायत सचिव

■ पंचायती राज किस सूची का विषय है?

- राज्य मूली

■ कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए 'वित्त आयोग' का गठन करता है?

- संबंधित राज्य का राज्यपाल

■ स्थानीय मैलों पर कर किसके द्वारा लगाया जाता है?

- ग्राम पंचायतों द्वारा

पेसा अधिनियम, 1996

संसद ने दिसंबर 1996 में 5वीं अनुसूची में शामिल जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों पर पंचायतों से संबंधित उपबंधों का विस्तार करने के लिए 'पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम' [The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996] पारित किया था। जनजातियों की विशेष स्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन एवं अपवाद के साथ भाग 9 को पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया ये वे अपवाद एवं परिवर्तन हैं जो कानून की धारा 4 में उल्लेखित हैं जो इस कानून को जनजातियों के लिए विशिष्टता प्रदान करते हुए उन्हें भिन्न प्रकार के अधिकार एवं विशेषाधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत निचले स्तर पर ग्राम सभा को सबसे मूल इकाई माना गया है और इसे लोगों की परंपराओं, रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान तथा समुदाय के संसाधनों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गयी है। इसमें लघु बनोपज का स्वामित्व, गांव-बाजारों का प्रबंधन, स्थानीय योजनाओं व संसाधनों पर नियंत्रण करने और स्थानीय विवादों को निपटाने की शक्ति ग्राम सभा को दी गयी है।

इटावा परियोजना

स्वतंत्रता के बाद एक विकास पहल के रूप में भारत ने 2 अक्टूबर, 1952 को गांधी जयंती की पूर्वसंध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया, जिसकी वृहत प्रेरणा अमेरीकी विशेषज्ञ अल्बर्ट मेरर द्वारा शुरू की गयी इटावा परियोजना (Etawah Project) से प्राप्त हुई थी। इस परियोजना की शुरुआत नवंबर 1948 में की गयी थी। इसमें करीब 97 गांवों को शामिल किया गया। इसमें ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया था, जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जाना था।

स्थानीय शासन

शहरी स्थानीय शासन

- भारत में आठ प्रकार की शहरी स्थानीय शासन, यथा- नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पत्तन न्यास, और विशेष उद्देश्य अभिकरण गठित किये जाते हैं। पहली नगरपालिका की स्थापना कब हुई थी?

- 1687-88 (मद्रास)
- 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9क जोड़ा गया, जिसे 'नगरपालिकाएं' नाम दिया गया तथा अनुच्छेद 243त (243P) से 243यछ (243ZG) के उपबंध शामिल किये गये। इस संविधान संशोधन द्वारा कौन-सी अनुसूची जोड़ी गयी? - 12वीं अनुसूची
- 12वीं अनुसूची में नगर नियोजन, भूमि के उपयोग का विनियमन, मार्ग एवं पुलों का निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, नगर वानिकी, गंदी बस्ती सुधार, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण जैसी कितनी मद्देशामिल हैं?

- 18 मद्देश
- प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करता है, जो जिले की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा योजना तैयार करता है। इसके 4/5 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? - जिला पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य
- ग्रामीण शहरी संबंध समिति (1963-66) ने सिफारिश की थी कि लघु क्षेत्रीय समितियों को पंचायती राज संस्थाओं में शामिल कर दिया जाना चाहिए ताकि स्थानीय निकाय के पैटर्न में दोहराव को रोका जा सके। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? - ए.पी. जैन
- महानगरीय क्षेत्र का अर्थ कितनी आबादी वाले क्षेत्र से है, जो (यह संख्या) एक या एक से अधिक जिलों या अधिक नगर महापालिकाओं या पंचायतों में हो सकती है?

- 10 लाख से अधिक
- नगरीय स्वशासन तीन प्रकार की होती है- नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम। वह क्षेत्र, जो ग्रामीण परिवेश से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, लेकिन पूर्ण रूप से नगर नहीं बना हो, क्या कहलाता है? - नगर पंचायत
- शहरी स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? - 5 वर्ष
- मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? - 5 वर्ष
- शहरी स्थानीय संस्थाओं को राज्य सरकार समय से पहले कदाचार या अक्षमता के आरोप में विघटित कर सकती है, किंतु कितने महीने के भीतर इनका चुनाव कराया जाना अनिवार्य है?

- 6 महीने
- किस अनुच्छेद के तहत शहरी स्थानीय संस्थाओं में जितने पद हैं (निर्वाचित पद), वे अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रखने का प्रावधान है?

- अनुच्छेद 243न(1)
- अनुच्छेद 243न(2) के अनुसार, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए जो स्थान आरक्षित हैं, उनमें से एक तिहाई स्थान किनके लिए आरक्षित हैं?

- इन जातियों की महिलाओं के लिए
- अनुच्छेद 243न(3) के अंतर्गत शहरी स्थानीय संस्थाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी हैं?

- एक-तिहाई
- तीन लाख से ऊपर की जनसंख्या पर नगरपालिका की स्थापना की जाती है। 10 लाख से अधिक की जनसंख्या पर किस शहरी संस्था की स्थापना की जाती है?

- नगर निगम
- नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? - महापौर (मेयर)
- संविधान की 12वीं अनुसूची में किस समिति का उल्लेख है, जो योजना आयोग (नीति आयोग) की पूरक संस्था के रूप में जिले के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करेगी एवं उसे राज्य सरकार को प्रेषित करेगी? - जिला योजना समिति

ई-पंचायत

ई-पंचायत वेब आधारित प्रणाली विकसित की गयी है, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं पारदर्शी करने के साथ-साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आंतरिक प्रक्रिया को भी सशक्त और सुव्यवस्थित करना है। यह मिशन मोड परियोजना (एनएमपी) की ऐसी परियोजना है, जिसका ग्रामीण भारत को सशक्त और रूपांतरित करने की दृष्टि से कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों को आधुनिकता, पारदर्शिता और कार्य-कुशलता के प्रतीक के रूप में रूपांतरित करना है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी सूचना प्रौद्योगिकी पहल में यह एक हिस्सा है, जिसका प्रयास कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेने, कार्यान्वयन और सुपुर्दगी में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना है।

ई-ग्राम स्वराज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल, 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर 'ई-ग्राम स्वराज' पोर्टल और एप लॉन्च किया। केंद्र सरकार के इस एप्लिकेशन के जरिए ग्राम पंचायतों की योजनाओं से लेकर खर्चे और सरपंच, पंचायती राज मंत्रालय ने इस एप्लिकेशन को बनाया है। इसके जरिए पंचायतों में किये गये कार्य की निगरानी आसानी से की जा सकती है। इससे पंचायत की गतिविधियों में सुधार आएगा और योजनाओं की व्यापकता बढ़ेगी।

किंविण NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? - अनुच्छेद 243भ
- अनुच्छेद 243झ के अधीन गठित कौन-सा आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है? - वित्त आयोग
- अनुच्छेद 243म(2) के तहत राज्यपाल वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गयी कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित किसके समक्ष रखवाता है? - राज्य विधानमंडल
- नगरीय संस्थाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व का निर्धारण कौन कानून बनाकर करता है? - राज्य विधानमंडल
- क्या दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे संघ राज्यक्षेत्रों में शाही स्वशासन के प्रावधान लागू होते हैं? - हाँ (अनुच्छेद 243यख)
- पंचायत और नगरीय स्वशासन में निर्वाचन संबंधी मामलों में क्या न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है? - नहीं (अनुच्छेद 243यछ)
- जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, जो राज्य सरकार के अधिकारिक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है? - जिलाधिकारी
- भारत में जिलाधिकारी का पद किस देश के प्रेफेक्ट के पद के समानांतर कहा जाता है? - फ्रांस
- जिलाधिकारी राज्य सरकार के प्रशासकीय विभाग से जुड़ा होता है, जिसका राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। प्रशासकीय मुखिया कौन होता है? - मुख्य सचिव
- जिलाधिकारी का सर्वप्रमुख कार्य राजस्व वसूल करना होता था। वह किसके अधीन कार्य करता है? - प्रमंडल आयुक्त
- जिले में कानून व्यवस्था कायम रखना भी जिलाधिकारी का प्रमुख कार्य होता है। इस कार्य के लिए वह किसके द्वारा नियंत्रित पुलिस बल को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है? - जिला पुलिस अधीक्षक
- जिला योजना क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? - जिलाधिकारी
- भूमि राजस्व कानून एवं क्रिमिनल प्रोसेजर कोड के अंतर्गत एक जिला को राजस्व एवं प्रशासन की सुविधा के लिए कई क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? - प्रमंडल
- एक प्रमंडल भी कई प्रशासकीय इकाइयों में विभक्त होता है। तहसील प्रशासन के कई रूपों, जैसे- राजस्व भूमि रिकॉर्ड, कोषागार की प्राथमिक इकाई है। इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? - लघु जिला
- (नोट: तहसील को लघु जिला इसलिए कहा जाता है कि इसमें कई विभागों के कार्यालय अवस्थित होते हैं।)
- तहसील में राजस्व वसूली एवं कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जिम्मेदार वह कौन-सा अधिकारी होता है जो राज्य सिविल सेवा से जुड़ा होता है एवं एक राजपत्रित अधिकारी होता है? - तहसीलदार
- प्रत्येक तहसील राजस्व प्रशासन में सुविधा की दृष्टि से कई इकाइयों में बंटा होता है, जिसको अंचल कहा जाता है। राजस्व प्रशासन के क्रम में प्रथम पद का निरीक्षक कौन होता है? - अंचलाधिकारी
- छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? - राष्ट्रपति
- कांजी हाउस और प्राणियों के प्रति क्रूरता के निवारण का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? - 12वीं अनुसूची

नगरीय शासन संबंधी संवैधानिक उपबंध

- अनुच्छेद 243त: परिभाषा।
- अनुच्छेद 243थ: नगरपालिका का गठन।
- अनुच्छेद 243द: नगरपालिका की संरचना।
- अनुच्छेद 243ध: बार्ड, समितियों आदि का गठन व संरचना।
- अनुच्छेद 243न: स्थानों का आरक्षण।
- अनुच्छेद 243प: नगरपालिका की अवधि।
- अनुच्छेद 243फ: सदस्यता के लिए निर्हताएं।
- अनुच्छेद 243ब: नगरपालिका की शक्तियां, प्राधिकार व उत्तरदायित्व।
- अनुच्छेद 243भ: नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां।
- अनुच्छेद 243म: वित्त आयोग।
- अनुच्छेद 243य: नगरपालिकाओं को लेखाओं की संपरीक्षा।
- अनुच्छेद 243यक: नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन।
- अनुच्छेद 243यख: संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना।
- अनुच्छेद 243यग: इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना।
- अनुच्छेद 243यघ: जिला योजना के लिए समिति।
- अनुच्छेद 243यड़: महानगर योजना के लिए समिति।
- अनुच्छेद 243यच: विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना।
- अनुच्छेद 243यछ: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप।

13

अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र

- संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र को नामित किया गया है। किस अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गयी है? - पांचवीं अनुसूची
- संविधान के किस अनुच्छेद में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न राज्यों में 'अनुसूचित क्षेत्र' कहलाने वाले कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध हैं, चाहे ऐसे क्षेत्र किसी राज्य में अवस्थित हों या संघ राज्यक्षेत्र में? - अनुच्छेद 244(1)
- वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान हैं? - नौ राज्य
(नोट: ये नौ राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान।)
- पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 और 7 के तहत संसद द्वारा बनाये गये विधान के अधीन रहते हुए किसको यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित कर दे? - राष्ट्रपति
- ऐसे राज्य, जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, वहां अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए परामर्श देने हेतु किस परिषद का गठन किया जाता है? - जनजाति सलाहकार परिषद
- जनजाति सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? - 20 सदस्य
- किसको यह अधिकार दिया गया है कि वह यह निर्देश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधानमंडल को कोई विशेष अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को लागू नहीं होगा अथवा अपवादों एवं उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा? - राज्यपाल
- राज्यपाल को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेगा। राज्यपाल द्वारा बनाये गये इस प्रकार के किसी भी विनियमन के लिए किसकी अनुमति प्राप्त करनी होती है? - राष्ट्रपति
- किस अनुच्छेद के अनुसार, राष्ट्रपति अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रत्येक 10 वर्ष के उपरान्त एक आयोग का गठन करेगा जो इन क्षेत्रों के प्रशासन एवं कल्याण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा? - अनुच्छेद 339
- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए संविधान में एक आयोग के गठन की व्यवस्था की गयी है। 1960 में पहले आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, जिसने अपना प्रतिवेदन 1961 में दिया? - यू.एन. डेवर
- अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से 10 जून, 1994 को किसकी अध्यक्षता में 22 विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था? - दिलीप सिंह भूरिया
(भूरिया समिति ने यह सिफारिश की कि जनजातीय क्षेत्रों में नये पंचायती राज का स्वरूप इस प्रकार हो कि परम्परागत संस्थाओं की नींव पर आधुनिक ढांचा निर्मित हो सके।)
- किस अनुच्छेद के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गयी है? - अनुच्छेद 244(2)
- किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है? - छठवीं अनुसूची

जनजातीय क्षेत्रों पर एक नजर

राज्य	जनजातीय क्षेत्र
1. असम	1. उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र
2. कार्बी आंगलोंग जिला	2. कार्बी आंगलोंग जिला
3. बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला	3. बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला
2. मेघालय	1. खासी पहाड़ी जिला
2. जर्यतिया पहाड़ी जिला	2. जर्यतिया पहाड़ी जिला
3. गारो पहाड़ी जिला	3. गारो पहाड़ी जिला
1. त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला	1. त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला
4. मिजोरम	1. चकमा जिला
	2. मारा जिला
	3. लाई जिला

पांचवीं अनुसूची

संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे इलाकों के रूप में परिभाषित करती है, जिन्हें राज्य के राज्यपाल के साथ विचार-विमर्श के साथ राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित इलाकों के रूप में घोषित किया जा सकता है। पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत कसी भी अनुसूचित इलाके के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड हैं-
(क) जनजातीय आबादी की प्रचुरता,
(ख) इलाके की सघनता और उपयुक्त आकार,
(ग) एक व्यवहार्य प्रशासिनक संस्था जैसे- जिला, ब्लॉक अथवा तालुक और
(घ) पड़ोसी इलाकों की तुलना में उस इलाके में आर्थिक पिछडापन। किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित इलाकों का विनिर्देश संबद्ध राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा किया जाता है। यही तरीका परिवर्तन, वृद्धि, कटौती, नये इलाकों को शामिल करने, अथवा अनुसूचित इलाकों से संबंधित किसी आदेश को रद्द करने के लिए लागू होता है।

छठी अनुसूची

संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के उन इलाकों

क्षिण NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- छठवों अनुसूची के अनुसार प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्यों की संख्या कितनी होगी? - चार
- जनजातीय क्षेत्रों को किस जिले के रूप में प्रशासित किया जाता है? - स्वशासी जिले के रूप में
- यदि किसी स्वशासी जिले में भिन-भिन अनुसूचित जनजातियां हों तो राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को, जिनमें वे बसे हुए हैं, किन क्षेत्रों में विभाजित कर सकेंगा? - स्वशासी प्रदेशों में
- जनजातीय क्षेत्रों में लोक अधिसूचना द्वारा नया स्वशासी जिला बनाने, किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने, दो स्वशासी जिलों को मिलाकर एक जिला बनाने, किसी स्वशासी जिले के नाम में परिवर्तन करने और किसी स्वशासी जिले की सीमाएं परिवर्तित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? - राज्यपाल
- तंसद किस विधान द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संवैधानिक के उपबंधों में परिवर्तन कर सकती है? - संविधान संशोधन के बजाय सामान्य विधान द्वारा
- जिला परिषदों को न्यायिक, सिविल और दार्ढिक शक्तियां होंगी। वे किस न्यायालय को अधिकारिता के इस प्रकार अधोन होंगे जो राज्यपाल समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें? - उच्च न्यायालय
- भूरिया समिति को सिफारिशों को स्वीकार करके भारत सरकार द्वारा पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक संसद में पारित किया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह अधिनियम कब से लागू हुआ? - 24 दिसंबर, 1996 से
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों के जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों हेतु विस्तारित किया गया? - अनुच्छेद 243D.
- क्या छठवों अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया गया है? - नहीं
- जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जातियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनका उचित अधिकार दिलाने के लिए, जो पोंडियों से जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन जिहें वन अधिकारों तथा वन भूमि में आजीविका से वंचित रखा गया है, कौन-सा अधिनियम लागू किया गया है? - अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम, 2006
- बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद भारत के असम राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसको कब एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया गया था? - फरवरी 2003 में
- बोडोलैंड के अंतर्गत असम के चार जिले- कोंकणाशाह, चिरांग, बक्सा और उदलगुरु आते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे के जिले हैं। इस क्षेत्र में किस जनजाति का बहुल्य है? - बर जनजाति (बोडो)
- किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में छठी अनुसूची सुरक्षा प्रदान किया गया? - 49वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1984
- 90वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान में कौन-सा अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें असम में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला सहित निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों तथा गैर-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखने का प्रावधान जोड़ा गया? - अनुच्छेद 332(6)
- अक्टूबर 2019 में मंधालय सरकार ने किन पांच 'अल्पसंख्यक जनजातियों' को संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों से बाहर कर 'अनारक्षित' श्रेणी में रखने का निर्णय लिया? - बोडो-कछारी, हाजोंग, कोच, मान तथा राभा जनजातियां

से है जिन्हें जनजातीय इलाकों के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे इलाकों के लिए जिला परिषदें अथवा क्षेत्रीय परिषदें प्रदान की गयी हैं। इन परिषदों का व्यापक कानूनी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गयी हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और गोवा पर्वतीय परिषदों को भी छठी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत स्वशासी जिला परिषदों की इन क्षेत्रों में स्थापना की जाती है।

मंधालय की पांच अल्पसंख्यक जनजातियां छठी अनुसूची से बाहा

अक्टूबर 2019 में मंधालय सरकार ने पांच अल्पसंख्यक जनजातियों को संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों से बाहर करने का निर्णय लिया। ये जनजातियां हैं— बोडो-कछारी, हाजोंग, कोच, मान तथा राभा। इनको मंधालय की स्वायत्त आदिवासी परिषदों में 'अनारक्षित जनजातियों' (Unrepresented Tribes) के रूप में नामांकित किया गया है। ये आदिवासी परिषदें गारो, खासी तथा जर्यतिया जनजातियों के नाम पर आधारित हैं, जो राज्य के तीन प्रमुख मातृसतात्मक समुदाय हैं। 26 सितंबर, 2019 को मंधालय राज्य सरकार द्वारा छठी अनुसूची में संशोधन के लिए गठित एक उप-समिति ने संशोधित विशेष प्रावधान से 'अनारक्षित जनजातियाँ' शब्द को हटाने हेतु संसद की स्थायी समिति से सिफारिश करने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन जनजातियों को स्वायत्त जिला परिषदों में संवैधानिक अधिकारों तथा प्रतिनिधित्व करने के अवसर से वंचित कर सकता है।

वनबंधु कल्याण योजना

भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने आदिवासियों के कल्याण के लिए वनबंधु कल्याण योजना (वीकंवाई) शुरू की है। इस योजना के लिए वित वर्ष 2015-16 में देश के आदिवासी अधिसूचित 10 राज्यों के 10 ब्लॉक को चुना गया। ये राज्य हैं— आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात।

14

केंद्र-राज्य संबंध

- भारत के संघीय शासन में राज्य (राजन) को समस्त शक्तियों दो सरकारों - केंद्र एवं राज्य के बीच विभाजित होती है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? - संघात्मक
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। भारतीय संघवाद को इस संकलन को किस देश को शासन व्यवस्था से लिया गया है? - कनाडा
- भारत में राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा राष्ट्रीय भारत भारतीय संविधान को बढ़ा संविधान का संघात्मक रूप एकात्मक रूप में बदल जाता है। इस दृष्टि से भारत को किस नाम से जाना जाता है? - अर्द्ध-संघात्मक या केंद्रित संघवाद
- केंद्र राज्यों के बीच संबंधों का बाणी भारतीय संविधान में कहां-कहां पाया जाता है? - आय 11 और 12 के अनुच्छेद 245 में 300 तक एवं एवी अनुसूची में विधायी संघर्ष
- केंद्र संकाय एवं राज्यों के मध्य विधायी संघर्ष को विवेचना किन अनुच्छेदों में को जाये है? - अनुच्छेद 245 से 255 तक
- संविधान के द्वाय केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया जाये है? - सातवीं अनुसूची में
- केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों के तहत किया गया है। इन सूचियों को क्या कहा जाता है? - मध्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची
- मध्य सूची में शामिल विषय किस प्रकार के होते हैं? - राष्ट्रीय महत्व के
- मध्य सूची में 97 विषय शामिल किये गये हैं, जैसे- युद्ध व शक्ति, विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक-जार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? - केवल संसद को
- राज्य सूची के द्वाय 66 विषय हैं। इन विषयों में लोक व्यवस्था एवं पुलिस, स्थानीय शासन, वृष्टि, बन सम्बद्ध, मन्त्र यात्रन आदि सम्मिलित हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार किसे हासिल है? - राज्य विधानपालिका को
- संविधान के किन उपवंशों के अधीन रहते हुए संसद सम्मूर्ण भारत राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण कर सकती है? - अनुच्छेद 245
- कौन-से दो अनुच्छेद विधायी शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं? - अनुच्छेद 245 एवं 246
- भारत में केंद्र-राज्य संबंध मुख्यतः किस पर निर्भर करते हैं? - सर्वीदारिक प्रावधानों, पारम्पराओं एवं न्यायिक व्याख्याओं पर
- केंद्र या संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। संसद को ऐसी शक्ति के द्वाय ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति भी प्राप्त है। इस अवशिष्ट विधायी शक्तियों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? - अनुच्छेद 248
- संविधान के किस उपवंश ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया? - अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ

भाग-11

संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय 1

विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255)

विधायी शक्तियों का वितरण

- **अनुच्छेद 245:** संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनायी गयी विधियों का विस्तार।
- **अनुच्छेद 246:** संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनायी गयी विधियों की विषय वस्तु।
- **अनुच्छेद 247:** कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति।
- **अनुच्छेद 248:** अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ।
- **अनुच्छेद 249:** राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति।
- **अनुच्छेद 250:** यदि आपात की उद्योगेण प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति।
- **अनुच्छेद 251:** संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनायी गयी विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनायी गयी विधियों में असंगति।
- **अनुच्छेद 252:** दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना।
- **अनुच्छेद 253:** अंतर्राष्ट्रीय करारों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना।
- **अनुच्छेद 254:** संसद द्वारा बनायी गयी विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनायी गयी विधियों में असंगति।

किंतु NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों (इकाइयों) को प्रदान की गयी हैं, जबकि भारतीय संविधान द्वारा ये शक्तियां किसको मिली हुई हैं? - केंद्र को किसके दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करने पर अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राष्ट्रहित में कानून बना सकती है? - राज्यमण्डा के प्रस्ताव में अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्रहित में पारित किया गया कानून कितने वर्षों तक प्रभावी रहता है?
- अनुच्छेद 250 के अनुसार, यदि आपात काल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? - संसद को अनुच्छेद 252 के अनुसार, यदि दो या अधिक राज्य यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि राज्य सूची में दिये गये विषय पर संसद कानून बनाये, तो संसद उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन इस प्रकार का कानून क्या सभी राज्यों पर लागू होगा? - नहीं, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन राज्यों ने प्रस्ताव किया है
- किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करने के लिए संसद राज्य सूची में दिये गये विषयों पर कानून बना सकती है? - अनुच्छेद 253
- समवर्ती सूची में 47 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिनमें विवाह, अनुवंध ट्रस्ट, श्रम कल्याण, आपाराधिक विधि एवं प्रक्रिया आदि शामिल हैं। इस सूची में वर्णित विषयों पर कौन विधान बना सकता है? - संघ एवं राज्य दोनों
- यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जायें तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी गयी है? - संघ सूची के विषय को

प्रशासनिक संबंध

- किस अनुच्छेद के अनुसार, केंद्र के प्रशासनिक अधिकार इसके विधायी क्षेत्र में आने वाले विषयों के अतिरिक्त किसी संधि या समझौते के अंतर्गत प्राप्त शक्ति से भी सम्बद्ध हैं? - अनुच्छेद 73
- राज्य की कार्यकारी शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने क्षेत्रों तक एवं उन विषयों तक है, जो उनके विधायी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? - अनुच्छेद 162
- किस अनुच्छेद में केन्द्र को एक सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा नया राज्य बनाने, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने एवं यहां तक कि राज्य का भौगोलिक अस्तित्व नष्ट कर देने के भी अधिकार दिये गये हैं? - अनुच्छेद 3 में
- किन अनुच्छेदों के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था की गयी है? - अनुच्छेद 256 से 263
- किस अनुच्छेद 256 में इस बात का उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जायेगा, जिससे संसद द्वारा बनायी गयी विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो? - अनुच्छेद 256
- किन अनुच्छेदों के तहत केन्द्र राज्यों को प्रशासनिक निर्देश भेज सकता है, जिसका उद्देश्य केन्द्र की कार्यकारी नीतियों का सहज कार्यान्वयन है? - अनुच्छेद 256 एवं 257 के तहत
- कृत्य संशर्त या बिना शर्त उसे सौंप सकता है? - राष्ट्रपति किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 258(क) जोड़कर यह प्रावधान किया गया सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, संशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा? - सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956
- किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार किसी ऐसे राज्यक्षेत्र की सरकार से जो भारत के राज्यक्षेत्र का भाग नहीं है, करार करके ऐसे राज्यक्षेत्र की सरकार में निहित किसी कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी? - अनुच्छेद 260

- अनुच्छेद 255: सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना।

अध्याय 2

प्रशासनिक संबंध

(अनुच्छेद 256-263)

साधारण

- अनुच्छेद 256: राज्यों की और संघ की वाध्यता।
- अनुच्छेद 257: कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण।
- अनुच्छेद 257क: राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा अन्य बलों की तैनाती में सहयोग (निरसित)।
- अनुच्छेद 258: कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति।
- अनुच्छेद 259: पहली अनुसूची के भाग वी में राज्यों में सशस्त्र बल (निरसित)।
- अनुच्छेद 260: भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता।
- अनुच्छेद 261: सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां।

जल संबंधी विवाद

- अनुच्छेद 262: अंतर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन।
- अनुच्छेद 263: अंतर्राज्यीय परियोग के संबंध में उपबंध।

भाग-12

वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद

(अनुच्छेद 264-300)

अध्याय 1

वित्त (अनुच्छेद 264-291)

साधारण

- अनुच्छेद 264: निर्वचन।
- अनुच्छेद 265: विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण (लागू) न किया जाना।
- अनुच्छेद 266: भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलंब।
- अनुच्छेद 267: आकस्मिकता निधि।

केंद्र-राज्य संबंध

- किस अनुच्छेद के तहत भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र, संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी गयी है? - **अनुच्छेद 261(1)**
भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिये गये अंतिम निर्णयों या आदेशों का कहां विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा?
 - किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी-दून के या उसके जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी? - **अनुच्छेद 262(1)**
 - अनुच्छेद 262(2) के तहत कौन यह उपबंध कर सकता है कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय अंतरराज्यिक नदियों से संबंधित किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा? - **मंसद**
 - अनुच्छेद 263 के तहत लोक हित की सिद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रपति अंतराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। अंतराज्यीय परिषद का गठन किस सरकार की सिफारिश पर 1989 में किया गया? - **वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार**
- वित्तीय संबंध**
- भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है? - **अनुच्छेद 264 से लेकर 291 तक**
 - किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जायेगा अन्यथा नहीं? - **अनुच्छेद 265**
 - भारत और राज्यों की सचित निधियों और लोक लेखे का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। भारत और राज्य की आकस्मिकता निधियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? - **अनुच्छेद 267**
 - किस अनुच्छेद के अनुसार, कुछ कर केंद्र सरकार अधिरोपित करती है और राज्य सरकार द्वारा वसूल किये जाते हैं और अपने पास रख लेते हैं, जैसे— स्टाम्प इयूटी, औषधीय एवं प्रसाधन निर्माण पर लगने वाले उत्पाद शुल्क आद? - **अनुच्छेद 268**
 - संघ द्वारा उद्गृहीत किये जाने वाले और संघ एवं राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किये जाने वाले सेवा कर का प्रावधान अनुच्छेद 268 के में किया गया है। इस अनुच्छेद को किस संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया?
 - **88वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003**
 - अनुच्छेद 269 के अनुसार, वे कर कौन-से हैं, जो केंद्र द्वारा लगाये व वसूल किये जाते हैं, पर राज्यों को सौंप दिये जाते हैं?
- **कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर, रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले जाने वाले माल तथा यात्रियों पर कर आदि**
 - अनुच्छेद 273 के तहत किन उत्पादों पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम का कोई भाग असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को सौंप दिये जाने के स्थान पर उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां भारित की जायेंगी जो विहित की जायें?
 - **जूट पर और जूट उत्पादों पर**
 - अनुच्छेद 274 के अनुसार, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होगी? - **राष्ट्रपति की**
 - अनुच्छेद 275 के अनुसार, विधि सम्मत अंतरण के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को क्या दिया जाता है? - **सहायता अनुदान**

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (अनुच्छेद 268-281)

- **अनुच्छेद 268:** संघ द्वारा उद्गृहीत किये जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किये जाने वाले शुल्क।
 - **अनुच्छेद 269:** संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर।
 - **अनुच्छेद 270:** संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किये जाने वाले कर।
 - **अनुच्छेद 271:** कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार।
 - **अनुच्छेद 272:** कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत किये जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किये जासकेंगे।
 - **अनुच्छेद 273:** जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान।
 - **अनुच्छेद 274:** ऐसे कराधान पर, जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा।
 - **अनुच्छेद 275:** कुछ राज्यों को संघ से अनुदान।
 - **अनुच्छेद 276:** वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर।
 - **अनुच्छेद 277:** व्यावर्ति।
 - **अनुच्छेद 278:** पहली अनुसूची के भाग वी में वित्तीय मामलों में राज्यों के साथ समझौता (निरसित)।
 - **अनुच्छेद 279:** 'शुद्ध आगम' आदि की गणना।
 - **अनुच्छेद 280:** वित्त आयोग।
 - **अनुच्छेद 281:** वित्त आयोग की सिफारिशों।
- प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध**
- (अनुच्छेद 282-291)**
- **अनुच्छेद 282:** संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किये जाने वाले व्यय।
 - **अनुच्छेद 283:** संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि।
 - **अनुच्छेद 284:** लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा।

किंवद्या NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- भारतीय जनता से संघ सरकार व राज्य सरकारें, संघीय सरकार की अनुमति से उधार ले सकती हैं। कौन-सी सरकार विदेशों से पैसा उधार ले सकती है? - **केवल केन्द्र सरकार**
- केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय साधनों के बट्टवारे से सम्बद्ध विषयों पर वित्त आयोग परामर्श देता है। यह किस प्रकार का निकाय है? - **अर्द्धन्यायिक निकाय**
- अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक पांच वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा एक सांविधानिक संस्था के रूप में किस आयोग की स्थापना की जाती है? - **वित्त आयोग की**
- वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है? - **हाँ, पुनर्नियुक्ति हो सकती है**
- वित्त आयोग मुख्यतः संघ और राज्य के बीच करों का वितरण, संचित निधि से राज्यों को सहायता, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों एवं राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कई अन्य विषय प्रमुख हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? - **राष्ट्रपति को**
- राष्ट्रपति अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गयी कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापना के साथ किसके समक्ष रखवाता है? - **संसद के दोनों सदनों के समक्ष**
- प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी. नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? - **एन.के. मिंह**
- 14वें वित्त आयोग की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री वाई.वी. रेड्डी ने की थी। इस आयोग ने केन्द्र सरकार के करों में राज्यों को कितना प्रतिशत हिस्सा देने की अनुशंसा की थी? - **42 प्रतिशत**
- राष्ट्रपति ने 22 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इस आयोग का कार्यकाल कब तक का है? - **वर्ष 2020-25 तक**
- 15वें वित्त आयोग ने दो नये केंद्रशासित प्रदेश (जम्मू व कश्मीर और लद्दाख) बनने के कारण वार्षिक रिपोर्ट (2020-21) तैयार की, जिसको संसद के पटल पर कब रखा गया? - **1 फरवरी, 2020 को**
- 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए दूसरी रिपोर्ट में अन्य सुझाव दिये जायेंगे। इस अंतिम रिपोर्ट को कब तक राष्ट्रपति को सौंपा जायेगा? - **30 अक्टूबर, 2020 तक**
- 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा कम करके कितना करने का सुझाव दिया है? - **मात्र 42 प्रतिशत**
- देश में योजनाओं के निर्माण के उद्देश्य से 15 मार्च, 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गयी थी। यह किस प्रकार की संस्था थी? - **संविधानेतर संस्था**
- योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यहां नीति (NITI) आयोग का पूरा रूप क्या है? - **डॉ. राजीव कुमार**
- **राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India)**
■ योजना आयोग की भाँति नीति आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है? - **प्रधानमंत्री**
■ नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। वर्तमान में इस आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? - **'सशक्त राज्य की सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं'** को स्वीकार करते हुए नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य राज्यों के सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से किस प्रकार के संघवाद को बढ़ावा देना है? - **डॉ. राजीव कुमार**
- किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात स्थिति लागू होने पर राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता कम हो जाती है तथा उन्हें दिये जाने वाले साविधिक अनुदानों को सीमित किया जा सकता है एवं केन्द्र, राज्यों को वित्तीय निर्देश भी भेज सकता है? - **अनुच्छेद 360**

- **अनुच्छेद 285:** संघ की सम्पत्ति को राज्य के करों से छूट।
- **अनुच्छेद 286:** माल के क्रय विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में प्रावधान।
- **अनुच्छेद 287:** विद्युत पर करों से छूट।
- **अनुच्छेद 288:** जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट।
- **अनुच्छेद 289:** राज्यों की सम्पत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट।
- **अनुच्छेद 290:** कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन।
- **अनुच्छेद 290क:** कुछ देवस्थम् निधियों का वार्षिक संदाय।
- **अनुच्छेद 291:** शासकों की प्रिवापर्स की राशि (निरसित)।

अध्याय 2

उधार लेना (अनुच्छेद 292-293)

- **अनुच्छेद 292:** भारत सरकार द्वारा उधार लेना।
- **अनुच्छेद 293:** राज्यों द्वारा उधार लेना।

अध्याय 3

सम्पत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं व वाद (अनुच्छेद 294-300)

- **अनुच्छेद 294:** कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों (Assets) अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार।
- **अनुच्छेद 295:** अन्य दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार।
- **अनुच्छेद 296:** राजगामी (उत्तराधिकारी के अभाव में सम्पत्ति पर राज्याधिकार) या व्यपगत (lapse) या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत सम्पत्ति।
- **अनुच्छेद 297:** राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मण्डल भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के सम्पत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना।
- **अनुच्छेद 298:** व्यापार करने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 299:** संविदाएं (करार)।
- **अनुच्छेद 300:** वाद और कार्यवाहियां।

अध्याय 4: सम्पत्ति का अधिकार

- **अनुच्छेद 300क:** विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को सम्पत्ति से वर्चित न किया जाना।

केंद्र-राज्य संबंध

- अनुच्छेद 301-304 के अंतर्गत किस संस्था को अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य व समागम को निर्वाचित कर सकती है? - संसद को किन दो अनुच्छेदों में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की सम्पत्ति पर राज्यों के करतथा राज्यों की सम्पत्ति और आय पर संघ के कराधान से छूट होगी? - अनुच्छेद 285 व 289
 - किस अनुच्छेद के तहत संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट मिलती है? - अनुच्छेद 285
 - अनुच्छेद 297 के तहत राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मण्डल भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य अर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) के संपत्ति ग्राहों का किसमें निहित होगा? - संघ में
 - अनुच्छेद 300 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। संपत्ति के अधिकार संबंधी इस प्रावधान को किस संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया?
- 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978**

संबंधित आयोग व समितियां

- प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-69) ने केंद्र-राज्य संबंधों के अध्ययन एवं इस पर सुझाव देने हेतु एम.सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने किस आधार पर राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने की संस्तुति की? - संविधान में संशोधन किये बिना
- वर्ष 1970 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने मुख्यतः राज्यपालों के क्रियाकलापों तथा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच के संबंधों पर अपनी सिफारिशें दीं। क्या इनकी सिफारिशों को स्वीकार किया गया?
- नहीं
- तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर, 1969 को किसकी अध्यक्षता में राज्यों को और अधिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित एक समिति गठित की, जिसने अवशिष्ट शक्तियों को समाप्त करने अथवा उसे राज्यों को दिये जाने, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने तथा अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी?
- डॉ. पी.वी. राजमन्नार
- वर्ष 1983 में केंद्र-राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय आयोग ने सिफारिश की थी कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहें? - न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया
- किस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हों या उसने हाल के वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो?
- सरकारिया आयोग
- सरकारिया आयोग ने किस अनुच्छेद के बारे में कहा कि इसमें ऐसे उपकरण हैं, जिनसे भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना सम्भव है? - अनुच्छेद 256
- 27 अप्रैल, 2007 को केंद्र-राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में गठित आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाना चाहिए?
- मदन मोहन पुछी
- पुछी आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद को अधिक प्रभावी बनाये जाने तथा उसका नाम बदलकर क्या करने की सिफारिश की थी? - राष्ट्रीय अर्थिक विकास परिषद किस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलाकर 'सर्वोच्च मंत्रिमंडल' बनाया जाये, जो केंद्र व राज्यों के मध्य साझे हित वाले मुद्दों पर विचार करे?
- पुछी आयोग

अंतर्राज्यीय परिषद

संविधान के भाग 11 के अनुसार अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में 'अंतर्राज्यीय परिषद' के गठन का अधिकार है। परिषद द्वारा किये जाने वाले कार्यों को सुनिश्चित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गयी है, परंतु संविधान में भी तीन कार्य बताये गये हैं, जो परिषद को सांप्रेक्षण करते हैं, ये हैं- राज्यों के बीच विवाद, उनकी जांच एवं उन पर सलाह। सरकारिया आयोग ने एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। अतः अप्रैल 1990 में इस परिषद की स्थापना की गयी। इसमें संघ के 6 मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का प्राथमिक उद्देश्य समन्वय और संघीय एकता स्थापित करना है। यह राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करती है और उन पर सलाह भी देती है।

जल विवाद प्राधिकरण

अनुच्छेद 262 के तहत जल विवादों को निपटाने के लिए संसद को यह अधिकार है कि वह जल विवाद प्राधिकरण स्थापित कर सकता है। यह प्राधिकरण राज्यों के बीच जल के बंटवारे, उनके उपयोग एवं नियंत्रण आदि से सम्बद्ध विवादों पर अपना निर्णय दे सकता है। जल विवाद से संबंधित जल विवाद प्राधिकरण के फैसले को उच्चतम न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

क्षेत्रीय परिषद

यह एक संविधाननेतर संस्था है। इसका उद्देश्य राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों और संघ के बीच परस्पर सहयोग एवं समन्वय द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गति सुनिश्चित करना है। इनका गठन 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम' द्वारा हुआ है। पूरे देश को उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। केन्द्रीय गृहमंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है एवं उस क्षेत्र में पड़ने वाले राज्य का मुख्यमंत्री तथा दो अन्य मंत्री, इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं।

15

संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं

लोक सेवाएं

- भारत में तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय बन सेवा। भारतीय बन सेवा को केन्द्रीय सेवा में कब शामिल किया गया? - 1966 में
- अखिल भारतीय सेवाएं संयुक्त रूप से केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं। इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यकारी केवल केन्द्र करता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? - मरदार पटेल को
- किस अनुच्छेद के तहत संसद और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वे संघ या किसी राज्य के कार्यकालप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए धर्ती एवं नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों का विनियमन कर सकें? - अनुच्छेद 309
- किस अनुच्छेद में संघ या राज्य सेवाओं में प्रसादपद्यन्त 'पद अवधारण के सिद्धांत' (Doctrine of Pleasure) का उल्लेख किया गया है? - अनुच्छेद 310
- प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई पद धारण करता है, तो वह किसके प्रसादपद्यन्त पद धारण करेगा? - राष्ट्रपति
- यदि कोई व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद पर धारण करता है तो वह किसके प्रसादपद्यन्त पद धारण करेगा? - उम गन्य के राज्यपाल
- अनुच्छेद 311 के तहत किसी भी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का अधिकार राज्य की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, किसके द्वारा उसको पदच्युत नहीं किया जा सकेगा? - उमकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किमी प्राधिकारी द्वारा
- नयी अखिल भारतीय सेवाओं के सूचन के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है। राज्यसभा यदि कोई प्रस्ताव पारित करे, तो नयी सेवा का गठन किस आधार पर हो सकता है? - 2/3 बहुमत से पारित मकाल्य पर
- अनुच्छेद 312(1) में निर्दिष्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत किस पद से नीच कोई पद नहीं होगा? - जिला न्यायाधीश (अनुच्छेद 236 में परिभाषित)
- कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने या वापस लेने को संसद की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 312क में किया गया है। इस अनुच्छेद को किस संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया?

- 28वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1972

लोक सेवा आयोग

- भारत में सबसे पहला लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर, 1926 को स्थापित किया गया था, जो वाद में जाकर संघ लोक सेवा आयोग बना। किसकी सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गयी थी? - लोक आयोग (1924)
- किस अधिनियम के उपवर्धों के अधीन संघ लोक सेवा आयोग को स्थापित कर लोक सेवा आयोग के कार्यों का और विस्तार किया गया? - भारतीय शासन अधिनियम, 1935
- संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक में किन आयोगों की स्वतंत्रता व शक्तियों तथा कार्यों, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, इनके संगठन आदि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? - संघ और राज्य लोक सेवा आयोग

भाग-14

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

(अनुच्छेद 308-323)

अध्याय-1

मेवाएं (अनुच्छेद 308-314)

- अनुच्छेद 308: निर्वचन।
- अनुच्छेद 309: संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की धर्ती और सेवा की शर्तें।
- अनुच्छेद 310: संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की दण्डवधि।
- अनुच्छेद 311: संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियंत्रित व्यक्तियों का परस्परत किया जाना, यदि से हटाया जाना या पक्षित में अवशत किया जाना।
- अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाएं।
- अनुच्छेद 312क: कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा जो शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें हटाने की संसद की शक्ति।
- अनुच्छेद 313: संकामयकालीन उपबधि।
- अनुच्छेद 314: जतिएव तंजओं के पहले से संवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान (निरसित)।

अध्याय-2

लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315-323)

- अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।
- अनुच्छेद 316: सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि।
- अनुच्छेद 317: लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलम्बित किया जाना।
- अनुच्छेद 318: आयोग के सदस्यों और कमचारियों को सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 319: आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर यद धारण करने के संबंध में प्रतिष्ठें।
- अनुच्छेद 320: लोक सेवा आयोगों के कृत्य।

संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं

- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? - भागन का गण्डपति
- संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? - गण्डपति द्वारा
- संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? - छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने तक
- संघ लोक सेवा आयोग को संसद की सेवाओं के अतिरिक्त भी कार्य दिये गये हैं। यह आयोग अपनी रिपोर्ट किसके सौंपता है? - गण्डपति को
- अनुच्छेद 315(1) के मुताबिक राज्यों में पृथक-पृथक लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान है। क्या दो या अधिक गम्य मिलकर एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित कर सकते हैं? - नहीं [अनुच्छेद 315(2)]
- अनुच्छेद 315(2) के तहत दो या अधिक गम्य यह करार कर सकते हैं कि गम्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा। इस आयोग क्या कहा जाता है? - संयुक्त आयोग
- संयुक्त आयोग के गठन के लिए संबंधित राज्यों को अपने-अपने विधानमंडल के मद्देन द्वारा या जहां दो मद्देन हैं तो वहां प्रत्येक मद्देन द्वारा संकल्प पारित कर किसके पास अंतिम संस्कृति के लिए भेजा जाता है? - संसद के पास
(नोट: तदापरांत संसद राज्यों की आवश्यकताओं की धूर्ति के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है।)
- सर्विधान में गम्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? - आयोग के सदस्यों की मात्रा भिन्न-भिन्न है
- राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति गम्यपाल करता है, परंतु उन्हें हटाने की शक्ति किसके पास है? - गण्डपति के पास
- संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? - गण्डपति द्वारा
- संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल इसे कहां प्रस्तुत करता है? - मर्विधि गम्य की विधानमंडल में
- संघ लोक सेवा आयोग में वर्ष 1990 से अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के गण्डपति द्वारा की जाती है? - तम अन्य सदस्य
- अनुच्छेद 316(1) के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, जिन्हें कितने वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो? - कम में कम 10 वर्ष
- संयुक्त आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है। वे कितने वर्ष की आयु तक पर पर रहे सकते हैं? - 62 वर्ष
- कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, क्या वह अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा? - नहीं [अनुच्छेद 316(3)]
- किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी गम्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा? - अनुच्छेद 319क
- किसी गम्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु किसके अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा? - भागन मर्कारा या किसी गम्य की मर्कारा के अधीन
- अनुच्छेद 317 में सदस्यों को अपदस्य करने की विधि का वर्णन किया गया है। नियुक्ति के बाद सरकार सदस्यों की सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकती और न ही उन्हें मनमाने तरीके से हटा सकती है। संघ या गम्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को किस आधार पर हटाया जा सकता है? - प्रमाणित दुरुचार के आधार पर

- अनुच्छेद 321: लोक सेवा आयोगों कार्यों का विस्तार करने की शक्ति।
- अनुच्छेद 322: लोक सेवा आयोगों के व्यव।
- अनुच्छेद 323: लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन।

भाग-14 क

अधिकरण (Tribunals)

- अनुच्छेद 323क: प्रशासनिक अधिकरण।
- अनुच्छेद 323ख: अन्य विषयों के लिए अधिकरण।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

भारतीय संसद द्वारा 1985 में पारित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal : CAT) और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत करता है। कैट की प्रमुख पीठ (बैंच) दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठें भी हैं। वर्तमान में 17 नियमित पीठ और 30 दिविजन बैंच हैं। कैट में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो न्यायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। सेवा की अवधि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाये, तक होती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कैट का कोई भी अन्य सदस्य अपने कार्यकाल के बीच में ही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को प्रेपित कर सकता है। कैट के अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवा का कोई भी एक सदस्य, संघ के किसी भी सिविल सेवा या संघ के तहत किसी भी सिविल पद पर नियुक्त एक व्यक्ति, रक्षा सेवाओं में नियुक्त कोई भी नागरिक या रक्षा से जुड़ा कोई भी एक पदधारी आता है; किंतु रक्षा बलों के सदस्य, अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट और संसद के सचिवालय के स्टाफ कर्मचारी कैट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। एक अधिकरण के पास उसी प्रकार की शक्तियां होती हैं जो सिविल प्रक्रिया सहित, 1908 की सहिता के तहत एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं।

- लोक सेवा आयोग के कार्यों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है - कार्यकारी, नियामक, तथा अर्द्ध-न्यायिक। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का उल्लेख किया गया है? - **अनुच्छेद 320**
 - संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय कोई वंतन, भत्ते और पेंशन आते हैं, किस निधि पर भारित होते हैं? - **भारत की संविधान निधि या राज्य की संचित निधि**
 - संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन किसको पेश करता है, जिसकी प्रति वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है? - **गान्धीपति को [अनुच्छेद 323(1)]**
 - राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। वह इस प्रतिवेदन को किसके समक्ष रखने का आदेश देता है? - **विधानमंडल [अनुच्छेद 323(2)]**
 - संविधान में ऐसा कोई उपवंध नहीं है, जिसके अनुसार सरकार को लोक सेवा आयोग का परामर्श मानने के लिए मजबूर किया जा सके, किंतु व्यवहार में सरकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है। लोक सेवा आयोग का कृत्य कैसा माना जाता है? - **मलाहकारी**
 - भारतीय संविधान यह अपेक्षा करता है कि संघ लोक सेवा आयोग किस पद्धति का प्रहरी हो? - **मंसिर पद्धति**
 - नागरिकों के लिए स्वयं को देश के प्रति वचनबद्ध करने हेतु वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? - **21 अप्रैल को**
- अधिकरण**
- संविधान में नवा भाग 14क जोड़ा गया, जिसे अधिकरण (Tribunals) नाम दिया गया। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया? - **42वाँ संविधान मणिधन अधिनियम, 1976**
 - अनुच्छेद 323क, जो प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, परंतु 323ख किससे संबंधित है? - **अन्य मामले के अधिकरण में**
(नोट: 323ख संसद तथा राज्य विधायिका कर संबंधी, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक श्रम, भूमि सुधार, नगर सम्पत्ति इत्यादि मामलों में अधिकरण बनाने का अधिकार देता है।)
 - अनुच्छेद 323क के अंतर्गत संसद ने वर्ष 1985 में कौन-सा अधिनियम पारित कर केन्द्र को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य को एक राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार प्रदान किया? - **प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985**
 - केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal) की प्रमुख पीठ (प्रिमिपल चैंच) दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसकी कितनी नियमित खंडपाठों हैं? - **17 खंडपाठ**
 - केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? - **एक अध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य**
 - कैट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवा अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, होती है। इसके अन्य मरम्मों की सेवा अवधि कितनी होती है? - **6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो**
 - केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, 1908 की सिविल प्रक्रिया सहित कानून की प्रक्रियाओं में वार्ध नहीं है। यह किस सिद्धांत से निर्दिष्ट होती है? - **प्राकृतिक न्याय के मिद्दांत पर**
 - किसी न्यायाधिकरण अथवा अधिकरण के आदेश के खिलाफ किस न्यायालय में अपील की जा सकती है? - **उच्च न्यायालय में (उच्चतम न्यायालय में नहीं)**
 - किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक अधिकरण के आदेश के खिलाफ सीधे मुक्त्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को पहले संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करना चाहिए? - **चंद्र कुमार मामले (1997) में**

कोई व्यक्ति अधिकरण में आवेदन कानूनी सहायता के माध्यम से या फिर स्वयं हाजिर होकर कर सकता है। किसी न्यायाधिकरण अथवा अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में तो अपील की जा सकती है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में नहीं।

भारत में गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण

1. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण; स्थापना वर्ष- 1969; संबंधित राज्य-महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
2. गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण; स्थापना वर्ष- 1969; संबंधित राज्य-महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा।
3. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण; स्थापना वर्ष- 1989; संबंधित राज्य-राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
4. कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण; स्थापना वर्ष- 1990; संबंधित राज्य-कर्नाटक, करल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी।
5. रावी जल विवाद न्यायाधिकरण; स्थापना वर्ष- 1986; संबंधित राज्य-पंजाब, हरियाणा।
6. द्वितीय कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण; स्थापना वर्ष- 2004; संबंधित राज्य-महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण

उच्चतम न्यायालय के 1992 के आदेश तथा विधि आयोग की संस्तुति के आधार पर संसद के द्वारा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 पारित करके इस न्यायाधिकरण का गठन किया गया। इसका गठन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आधार पर हुआ। 2009 में स्थापित इस न्यायाधिकरण की नयी दिल्ली में एक प्रधान पीठ है, जबकि जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में क्षेत्रीय बंच स्थापित किये गये हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके न्यायिक सदस्य होते हैं। इसके पास नियुक्तियाँ, कमीशन, नामांकन और सेवाओं की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के स्थगन या परीक्षण की शक्ति है।

संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं

भारतीय प्रशासनिक सेवा में लैटरल एंट्री

जुलाई 2017 में केंद्र सरकार ने नौकरशाही में सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के अलावा लैटरल एंट्री (Lateral Entry) से प्रवेश का प्रावधान यानी सीधी नियुक्ति करने पर विचार करने की बात कही थी। उसका मानना है कि निजी क्षेत्र के अनुभवी उच्चाधिकारियों को विभिन्न विभागों में उपसचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नियुक्त कर उनके अनुभव एवं विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में जब प्रशासनिक सुधारों के लिए पहली रिपोर्ट पेश की गयी, उस समय भी नौकरशाही में लैटरल एंट्री का पहला प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद वर्ष 2010 में दूसरी प्रशासनिक सुधार परिपोर्ट में भी इसकी अनुशंसा की गयी। हालांकि पहली गम्भीर पहल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2016 में इसकी सम्भावना तलाशने के लिए एक समिति बनायी, जिसने अपनी रिपोर्ट में इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की अनुशंसा की। इसी क्रम में डीओपीटी की ओर से 10 जून, 2018 को एक अधिसूचना जारी कर 10 विभागों में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये। इस अधिसूचना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं—

- मंत्रालयों में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति होगी। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और यदि प्रदर्शन अच्छा हुआ, तो 5 वर्ष तक के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है।
- इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गयी है, जबकि न्यूनतम उम्र 40 वर्ष है।
- इनका वेतन केंद्र सरकार के अंतर्गत संयुक्त सचिव वाला ही होगा तथा सारी सुविधाएं उसी के अनुरूप मिलेंगी। इन्हें सर्विस रूल की तरह काम करना होगा।
- इस पद पर चयन के लिए केवल साक्षात्कार देना होगा और कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में बनने वाली समिति इनका साक्षात्कार लेंगी।

इस अधिसूचना के अनुसार, निजी क्षेत्र के 9 विशेषज्ञों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों (वित्त सेवा, आर्थिक मामले, कृषि, सड़क परिवहन, जहाजरानी, पर्यावरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उद्योग और वाणिज्य) में संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्त किया गया है।

ज्ञातव्य है कि नीति आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि यह जरूरी है कि लैटरल एंट्री के तहत विशेषज्ञों को मिस्टम में शामिल किया जाये। इसका उद्देश्य ब्यूरोक्रेसी को गति देने के लिए निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों की तलाश करना था। वैसे भी वैश्वीकरण ने शासन के काम को अत्यंत जटिल बना दिया है, इसलिए क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों और कौशल की आवश्यकता पड़ रही थी। अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक-टैक की जरूरत और भी ज्यादा महसूस की जा रही थी। विदेश मंत्रालय ने भी बाहरी उम्मीदवारों को अल्पकालिक अनुबंध पर रखने की बात कही थी।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्हें लैटरल एंट्री के तहत ही 1971 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार और 1972 में वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया और यह पद भी संयुक्त सचिव स्तर का ही होता है। इसी प्रकार रघुराम राजन को प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया और वे भी यूपीएससी से उनकर नहीं आए थे, लेकिन संयुक्त सचिव के स्तर तक पहुंच गये थे। इसी आधार पर इन्फोसिस के नंदन निलेकणी को भी आधार कार्ड जारी करने वाली संवैधानिक संस्था यूआईडीएआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। यह सूची बहुत लंबी है जो बिमल जालान, उर्जित पटेल, डॉ. वर्गोज कुरियन (एनडीबीबी चेयरमैन), सैम पित्रोदा, मार्टेक सिंह अहलूवालिया, राकेश मोहन, योगिंदर अलघ, विजय कोलकर आदि तक जाती है।

सिविल सेवा में सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियां एवं आयोग

- **सन्थानम् समिति:** अध्यक्ष- के. सन्थानम्; वर्ष- 1964; उद्देश्य- प्रशासनिक सेवाओं और जिला प्रशासन की समस्याएं।
- **कोठारी आयोग:** अध्यक्ष- डॉ. एस. कोठारी; वर्ष- 1976; उद्देश्य- भारतीय सिविल सेवा परीक्षा और भर्ती संबंधी नीतियों और विधियों का निर्धारण; सिफारिश- त्रिस्तरीय सिविल सेवा परीक्षा, यथा- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण का सुझाव। इसी के आधार पर वर्तमान में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
- **सतीश चंद्रा समिति:** अध्यक्ष- सतीश चंद्रा; वर्ष- 1989; गठन- सिविल सेवा परीक्षा पद्धति की समीक्षा के लिए; सिफारिश- इस समिति की सिफारिश पर निबंध का प्रश्न पत्र जोड़ा गया और साक्षात्कार के अंकों में वृद्धि की गयी।
- **अलघ समिति:** अध्यक्ष- वाई. के. अलघ; वर्ष- 2000; उद्देश्य- सिविल सेवा परीक्षा पद्धति के मूल्यांकन एवं इनमें सुधार के लिए सुझाव देना; सिफारिश- प्रारंभिक परीक्षा में दो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न पत्र हों, जिसमें एक वैकल्पिक विषय और दूसरा सिविल सेवा एप्टीद्यूट टेस्ट हो।
- **होता समिति:** अध्यक्ष- पी.सी. होता; वर्ष- 2002-04; सिफारिश- सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए तथा सिविल सेवा को अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार रहित बनाना चाहिए।
- **दूसरा प्रशासनिक आयोग:** अध्यक्ष- वीरपा मोइली; वर्ष- 2005; सिफारिश- सिफारिशों मुख्यतः प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में परिवर्तन से संबंधित थीं, जिन्हें 2011 में प्रारंभिक परीक्षा में और 2013 में मुख्य परीक्षा में परिवर्तन करके लागू किया जा चुका है।
- **बासवान समिति:** अध्यक्ष- बी.एस. बासवान; वर्ष- 2016; सिफारिश- इस समिति ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव दिया है।

16

चुनाव एवं निर्वाचन आयोग

- निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना है। इसकी स्थापना कब की गयी थी? - 25 जनवरी, 1950 को
- संविधान के कौन-से अनुच्छेद निर्वाचन, चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, कार्यों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं? - अनुच्छेद 324 से 329 तक
- किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में होगा? - अनुच्छेद 324(1)
- संविधान के किन अनुच्छेदों में निर्वाचन आयोग की रचना का वर्णन किया गया है? - अनुच्छेद 324(2), (3) और (4) में
- चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त दो अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? - राष्ट्रपति
- चुनाव आयोग को सहायता देने के लिए लोकसभा वराज्य विधानमंडलों के चुनाव सेपूर्व किसको प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार होगा? - राष्ट्रपति को
- राष्ट्रपति किसकी सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है? - निर्वाचन आयोग
- निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाये, होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार हटाया जाता है? - मंसद द्वारा विशेष बहुमत से (जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है)
- उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कदाचार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाये गये प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। उपरोक्त पदों से किसी को हटाने के लिए संविधान में 'महाभियोग' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल किसको उसके पद से हटाने के लिए किया जाता है? - राष्ट्रपति
- निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए इसे पहली बार कब तीन सदस्यीय बना दिया गया?
- इसके बाद कुछ समय के लिए इसे फिर से एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। कब से पुनः इसका तीन सदस्यीय आयोग बाला स्वरूप बहाल कर दिया गया और तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं? - 1 अक्टूबर, 1993 में
- चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने संबंधी विधेयक को संसद ने कब पारित किया गया? - 20 दिसंबर, 1993 को
- 14 जुलाई, 1995 को किस न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए टीएन शेपन व अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों को एक समान दर्जा देने की व्यवस्था संबंधी राष्ट्रपति के अध्यादेश को वैध ठहराया? - उच्चतम न्यायालय ने
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के बेतन, भत्ते व सेवा की शर्तों में उनके कार्यकाल में कोई परिवर्तन किया जा सकता है?
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद ग्रहण करते समय क्या कोई शपथ लेनी पड़ती है? - नहीं

भाग-15

निर्वाचन (अनुच्छेद 324-329)

- **अनुच्छेद 324:** निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।
- **अनुच्छेद 325:** धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किये जाने का दबा न किया जाना।
- **अनुच्छेद 326:** लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना।
- **अनुच्छेद 327:** विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपवंध करने की संसद की शक्ति।
- **अनुच्छेद 328:** किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपवंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति।
- **अनुच्छेद 329:** निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।
- **अनुच्छेद 329क:** प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले (निरसित)।

भारत के राष्ट्रीय पार्टियों की मूर्चा

(7 फरवरी, 2020 तक की स्थिति)

1. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), स्थापना- 1980, चिह्न- कमल का फूल।
2. बहुजन समाज पार्टी (बसपा), स्थापना- 1984, चिह्न- हाथी।
3. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम), स्थापना- 1964, चिह्न- हथौड़ा, हसिया एवं तारा।
4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), स्थापना- 1925, चिह्न- हसिया एवं मक्के की बाली।
5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), स्थापना- 1885, चिह्न- हाथी।

चुनाव एवं निर्वाचन आयोग

पहले चुनाव संबंधी सभी चुनाव याचिकाएं चुनाव आयोग के सामने पेश होती थीं और चुनाव आयोग ही उनका निर्णय करने के लिए चुनाव न्यायाधिकरण नियुक्त करता था, परंतु अब चुनाव मामलों में याचिका सुनने का अधिकार किसको प्राप्त हो गया है?

- उच्च न्यायालयों को

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी झगड़े किसके द्वारा सुने जाते हैं?

- उच्चतम न्यायालय

वर्ष 1969 में राष्ट्रपति वीवी गिरि के चुनाव के संबंध में की गयी चुनाव याचिका का निर्णय किसने किया था?

- उच्चतम न्यायालय

राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता के बारे में कौन परामर्श देता है?

- चुनाव आयोग

चुनाव आयोग विभिन्न दलों को चुनाव चिह्न प्रदान करता है, लेकिन चुनाव चिह्नों से संबंधित झगड़ों को कौन निपटाता है?

- स्वयं चुनाव आयोग

चुनाव आयोग द्वारा बहु-उद्देश्यीय पहचान पत्र और चुनाव याचिकाओं को शीघ्र निपटाने के लिए किनकी नियुक्ति की सिफारिश की गयी थी?

- तदर्थ न्यायाधीशों की

चुनाव आयोग ने कब राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि मतदाताओं को मतदान पहचान पत्र जारी किये जायें, जिससे जाती मतदान से बचा जा सके? - नवंबर 1993 में

चुनाव आयोग की दिशा-निर्देश के मुताबिक, लोकसभा सीट के लिए किन तीन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम 70 लाख रुपये खर्च कर सकता है?

- अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम

(नोट: लोकसभा चुनाव में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम में खर्च की अधिकतम सीमा 54 लाख रुपये है। यह दिल्ली के लिए 70 लाख रुपये और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 54 लाख रुपये है।)

विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में निर्वाचन व्यवहार की उच्चतम सीमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र आठ राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुर्णचरी) के लिए 20 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। शेष राज्यों के लिए यह सीमा कितनी रखी गयी है?

- 28 लाख रुपये

किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकृत किया गया चन्दा निर्वाचन आयोग के समक्ष निर्दिष्ट प्रपत्र में घोषित किया जाना चाहिए?

- निर्वाचन एवं अन्य सम्बद्ध विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003

किस अधिनियम के तहत परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 11 और जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 9 में संशोधन किया गया है?

- चुनाव अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2016

समस्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? - चुनाव आयोग

वर्ष 1989 में की गयी व्यवस्था के तहत किस अधिनियम के अनुसार सभी राजनीतिक दलों के लिए संविधान के प्रति और समाजवाद, पंथनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के प्रति निष्ठा घोषित करना जरूरी है?

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत मतदाताओं की अयोग्यता, मतदाता सूची और अन्य संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत चुनाव और उपचुनावों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किये गये हैं?

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किये जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है? - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विनिर्दिष्ट

लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त हो?

- 1/6 से कम मत प्राप्त हों

वह निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है, जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल विविध राजनीतिक दलों की शक्ति प्रतिविवित करता है?

- आनुपातिक प्रतिनिधित्व

6. राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), स्थापना- 1999, चिह्न- घड़ी।

7. तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी), स्थापना- 1998, चिह्न- फूल एवं घास।

8. नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी), स्थापना- 2013, चिह्न- पुस्तक।

राष्ट्रीय राजनीतिक दल

राष्ट्रीय पार्टी: एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी (National Party) का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है जब वह निम्नलिखित तीन में से किसी एक शर्त को पूरा करती हो-

1. यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें (2014 के चुनाव के अनुसार 11 सीटें) जीतती है, अथवा

2. यदि कोई 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती हो, अथवा

3. यदि कोई पार्टी चार या चार से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती हो।

राज्य स्तरीय पार्टी: एक पार्टी को राज्य स्तरीय दल (State Party) का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है जब वह निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम किसी एक शर्त को पूरा करती हो-

1. यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा को कुल सीटों में से कम-से-कम 3% सीट या कम-से-कम 3 सीटें, जो भी ज्यादा हो प्राप्त करती है, या

2. यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीट प्राप्त करती है, या

3. यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम से कम 6% मत प्राप्त करती है और साथ ही कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतती है।

क्षेत्रीय पार्टी: यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल

किंवद्दन NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 में संशोधन करते हुए राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता के लिए नये मानदंड का निर्धारण किया? - वर्ष 2000 में (1 दिसंबर)
- यदि कोई राजनीति दल लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गये वैध मतों का 60% प्राप्त करने के साथ ही साथ किसी राज्य में लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करता है अथवा लोकसभा में उसे कम से कम 20% सीटें अर्थात् कम से कम लोकसभा की 543 सीटों में से 11 सीटों को जीता है तथा चार या चार से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है तो उसे किस दल की मान्यता मिलती है? - राष्ट्रीय दल
- वर्तमान समय में भारत में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पार्टीयों की संख्या कितनी है? - आठ
- किस पार्टी को वर्ष 2019 में चार राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड और मेघालय में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली और उत्तर-पूर्वी राज्यों से पहली राष्ट्रीय पार्टी बनी?
- - नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)
- किस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा आरक्षण का प्रावधान किया गया है? - परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 एवं 1972
- जनसंख्या के नये आंकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का नये रूप में सीमाबद्ध एवं विभाजन करना किस आयोग का कार्य है? - परिसीमन आयोग
- वह पहला राज्य कौन-सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? - कर्नाटक
- लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किस अवधि तक नियत कर दिया जाता है?
- - सन् 2026
- वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? - सुनील अरोड़ा
- निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक, सलाहकारी एवं अर्द्धन्यायिक प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। इस आयोग का सचिवालय कहां स्थित है? - नयी दिल्ली में
- अनुच्छेद 326 के अनुसार, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। भारत का प्रत्येक नागरिक कितने वर्ष का होने पर मतदान का अधिकारी होता है? - 18 वर्ष का
- किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार को आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गयी? - 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1989
- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 के तहत किन व्यक्तियों को मताधिकार से अयोग्य घासित किया गया है? - अनिवार्मी, विकृत चिन्त, अपराधी, भ्रष्ट या अवैध आचरण वाले व्यक्तियों को
- कब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर प्रवासी भारतीयों को संसद और राज्य विधानसभाओं में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? - सितंबर 2010 में
- लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? - 30 वर्ष
- भारत 'लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान' (आईडीईए) का एक संस्थापक सदस्य है। इस संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? - स्टॉकहोम, स्वीडन
- लोकतंत्रिक एवं निर्वाचन प्रक्रियाओं में मतदाता सहभागिता किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष में निर्वाचन प्रबंधन के अभिन्न अंग के रूप में मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता को औपचारिक रूप से अपनाया है? - वर्ष 2009 में
- चुनाव आयोग सचिवालय का अपना एक स्वतंत्र बजट होता है, जिसे आयोग और संघ सरकार के किस मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है? - वित्त मंत्रालय
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34(1ए) के अनुसार, 'संसदीय निर्वाचन क्षेत्र' के लिए चुनाव लड़ने हेतु 25 हजार रुपये की जमानत राशि होती है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए यह राशि कितनी है? - 10 हजार रुपये

रहती है, किंतु वह उस राज्य में डाले गये कुल वैध मतों में से 8% मत प्राप्त करती है, तो उस राज्य में उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है।

वीबीपीएटी मशीन क्या है?

वीबीपीएटी (Voter Verifiable Paper Audit Trail) एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो इवीएम के साथ अटैच होती है। जब मतदाता वोट डालता है, उस समय वीबीपीएटी में एक पर्ची जनरेट होती है, जिसको स्क्रीन पर 7 सेकेंड के लिए देखा जा सकता है। इसके बाद यह पर्ची बॉक्स में लॉक हो जाती है। वोट डालने के बाद मतदाता अपने डाले हुए वोट को देख सकता है, इससे उसे संतुष्टि होती है कि उसने जिसको वोट किया है, उसका मत उसी को मिला है या नहीं। इस मशीन के द्वारा मतगणना में यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की सम्भावना होती है, उस परिस्थिति में वीबीपीएटी मशीन के द्वारा जनरेट पर्ची की गिनती कर के ऑडिट किया जा सकता है। इससे चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बन जाती है। वीबीपीएटी मशीन का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया है। सर्वप्रथम इस मशीन का डिजाइन वर्ष 2013 में तैयार किया गया था और सबसे पहला इसका प्रयोग वर्ष 2013 में ही नगालैंड के विधानसभा चुनाव में किया गया था। यह परीक्षण सफल साबित होने के बाद उच्चतम न्यायालय ने वीबीपीएटी मशीन बनाने और इसके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश जारी किया।

पिंक बूथ क्या है?

चुनाव आयोग ने 2018 में सुधारों के तहत 'पिंक बूथ' के जरिए एक और नया प्रयोग किया। इसका उद्देश्य महिला मतदाताओं को बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित करना है। इन मतदान केंद्रों को गुलाबी रंगों में सजाया जाता है और कर्मचारियों को गुलाबी ड्रेस दी जाती है। साथ ही इन बूथों पर तैनात सभी कर्मचारी, जिनमें पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी

चुनाव एवं निर्वाचन आयोग

- संसद द्वारा कब जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में एक नयी धारा जोड़कर चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के उपयोग का अधिकार दिया गया?
- दिसंबर 1988 में
- प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का पहली बार उपयोग वर्ष 1998 में किन तीन राज्यों के चुनावों के दौरान किया गया था?
- राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली
- वर्ष 1999 में किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का पूरे राज्य में प्रयोग हुआ?
- गोवा
- भारत में मतदाताओं ने सबसे पहले किस लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए मत डाले थे?
- लोकसभा चुनाव, 2004
- निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए वीवीपीएटी (VVPAT) मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से 7 सेकेंड के लिए मतदाता यह देख सकेंगे कि उन्होंने अपना मत किसको दिया। वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या है?
- वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रैल (Voter Verifiable Paper Audit Trail)
- वीवीपीएटी मशीन का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम इस मशीन का प्रयोग किस चुनाव में किया गया?
- वर्ष 2013 में नगालैंड के विधानसभा चुनाव में
- भारत में निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सबसे पहले नोटा का प्रयोग किया था। किस वर्ष में इसे सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया?
- वर्ष 2015 में
- नोटा (NOTA) का पूरा रूप क्या है? - **None of the Above** (इसमें से कोई नहीं)
- नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश ने अपने नेवादा राज्य में वर्ष 1976 के चुनाव में किया था?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में 'आदर्श आचार संहिता' कौन जारी करता है, ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाये?
- चुनाव आयोग
- निर्वाचन आयोग ने पहली बार किस चुनाव में आचार संहिता (Code of Conduct) लागू की थी?
- 1971 में 5वीं लोकसभा चुनाव में
- आचार संहिता के समय कई प्रकार से लोगों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है। चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का नागरिकों द्वारा रिपोर्ट किये जाने की सुविधा देने के लिए निर्वाचन आयोग ने कौन-सा एप लॉन्च किया है?
- सी-विजिल (C-VIGIL) एप
- वर्ष 1966 के बाद से उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है?
- कम से कम 20 दिन का
- मतदान की तारीख के कितने घंटे पहले चुनाव अभियान या प्रचार बंद कर दिया जाता है?
- 48 घंटे पहले
- महिला मतदाताओं को बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने किस वर्ष से 'पिंक बूथ' के जरिए एक नया प्रयोग किया है? - वर्ष 2018 से
- राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 का अपमान करने पर कितनी अवधि तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है?
- 6 वर्ष तक
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान की शुरुआत होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक किस प्रकार के पोल को प्रतिबंधित कर दिया है?
- एक्विट पोल को
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के दौरान एक्विट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर किस सजा का प्रावधान किया गया है?
- दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों

भी शामिल होते हैं, सभी महिलाएं होती हैं, यहाँ तक की सुरक्षाकर्मी भी महिलाएं होती हैं। इन बूथों का इस्तेमाल कई चुनावों में सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

चुनाव सुधार से संबंधित समितियां एवं आयोग

- **तारकुंडे समिति (1974-75):** अगस्त 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बम्बई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश वी.एस. तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। **प्रमुख सिफारिशें-** मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाये तथा सरकार की ओर से मतदाताओं को निःशुल्क मतदान कार्ड दिया जाये।
- **दिनेश गोम्बारी समिति (1990):** राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने तत्कालीन विधि मंत्री दिनेश गोम्बारी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया। **प्रमुख सिफारिशें-** मतदान केंद्र पर कब्जे की घटनाओं को रोकने के लिए पुनर्मतदान कराये जायें तथा ईवीएम मशीनों का प्रयोग प्रारंभ किया जाये।
- **बोहरा समिति (1993):** राजनीति के अपराधिकरण पर 1993 में तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव एनएन बोहरा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मुंबई में सीरियल विस्फोट के बाद जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में आए तथ्यों के बाद इसका गठन किया गया था। **प्रमुख बातें-** राजनेताओं द्वारा आपराधिक गैंग का संचालन किया जा रहा है। अपराधी अब सांसद और विधायक बनने लगे हैं। समिति के अनुसार सीबीआई, आईबी, रो सहित अनेक एजेंसियों ने सर्वसम्मति से अपनी राय व्यक्त की थी कि आपराधिक नेटवर्क बस्तुतः समानांतर सरकार चला रहा है।
- **इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998):** जून 1998 में भाकपा के इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसने अगस्त 2000 में अपनी सिफारिशें दीं। **प्रमुख सिफारिशें-** चुनावों में राज्य वित्तपोषण हो अर्थात् राजनीतिक पार्टियों को चुनाव

किंवद्दण NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

मुख्य चुनाव आयुक्त और उनका कार्यकाल

सुकुमार सेन
कंवीके सुन्दरम
एसी सेन वर्मा
डॉ. नगन्द्र सिंह
टी. स्वामीनाथन
एसएल शक्थर
आरके त्रिवेदी
आरबीएस पंरीशास्त्री
श्रीमती वीएस रमादेवी (कार्यवाहक)
टीएन शेषन
एमएस गिल
जेएम लिंगदोह
टीएस कृष्णापूर्ण
बीबी टण्डन
एन. गोपालास्वामी
नवीन चावला
एसवाई कुरेशी
वीएस सम्पत
एचएस ब्रह्मा
नसीम जैदी
अचल कुमार जांति
ओम प्रकाश रावत
सुनील अरांड़ा

21 मार्च, 1950 से 19 दिसंबर, 1958
20 दिसंबर, 1958 से 30 सितंबर, 1967
1 अक्टूबर, 1967 से 30 सितंबर, 1972
1 अक्टूबर, 1972 से 6 फरवरी, 1973
7 फरवरी, 1973 से 17 जून, 1977
18 जून, 1977 से 17 जून, 1982
18 जून, 1982 से 31 दिस., 1985
1 जनवरी, 1986 से 25 नवंबर, 1990
26 नवंबर, 1990 से 11 दिसंबर, 1990
12 दिसंबर, 1990 से 11 दिसंबर, 1996
12 दिसंबर, 1996 से 13 जून, 2001
14 जून, 2001 से 7 फरवरी, 2004
8 फरवरी, 2004 से 15 मई, 2005
16 मई, 2005 से 29 जून, 2006
30 जून, 2006 से 20 अप्रैल, 2009
21 अप्रैल, 2009 से 29 जुलाई, 2010
30 जुलाई, 2010 से 10 जून, 2012
11 जून, 2012 से 15 जनवरी, 2015
16 जनवरी, 2015 से 18 अप्रैल, 2015
19 अप्रैल, 2015 से 6 जुलाई, 2017 तक
6 जुलाई, 2017 से 22 जनवरी, 2018
23 जनवरी, 2018 से 1 दिसंबर, 2018
2 दिसंबर, 2018 से अब तक

में व्यय के लिए धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाये। चुनाव व्यय के लिए एक सार्वजनिक कांप स्थापित करना चाहिए, जिसमें सरकार को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपये योगदान करना चाहिए। 10,000 से अधिक चंदे को राशि ड्राफ्ट अथवा चंके के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था हो।

- **के संथानम समिति:** इंद्रजीत गुजा समिति के बाद चुनाव सुधारों के लिए के संथानम समिति का गठन हुआ। **प्रमुख सिफारिशें-** निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को व्यवस्था हो तथा समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाये।
- **विधि आयोग की रिपोर्ट (1999):** वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन किया था। इस रिपोर्ट में दलाय सुधारों की बात भी कही गयी है। राजनीतिक दलों के कांप, चंदा एकत्रित करने के तरीके और उसमें अनियमितताएं तथा इन सबका राजनीतिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव आदि का भी इस रिपोर्ट में विस्तृत किया गया है। आज इवीएम में नोटों का जो विकल्प है, उसको सिफारिश भी विधि आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में नकारात्मक मतदान की व्यवस्था लागू करने की बात कहकर की थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यह विकल्प मतदाताओं को दिया गया।
- **चुनाव आयोग की रिपोर्ट (2004):** चुनाव आयोग ने भी चुनाव सुधारों पर बहुमूल्य प्रस्ताव वर्ष 2004 में पेश किये। इस प्रस्ताव में उसने सभी राजनीतिक दलों के खातों को सार्वजनिक करने की अपील की थी।

वीरपा मोइली समिति (2007) और तनखा समिति (2010) ने भी चुनाव कानूनों और चुनाव सुधार पर अपनी सिफारिशें दी थीं। इन समितियों और आयोगों की सिफारिशोंके आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किये गये हैं।